जशपुर जिले की प्रथम मासिक पत्रिका | मूल्य – ₹20 /-

पंजीयन संख्या : RNI - CHHHIN/25/A0341

निर्भीक स्वतंत्र आवाज

जशपुर की आवाज

jashpurvaninews@gmail.com

वर्ष – 01, अंक – 03 | मासिक पत्रिका – जुलाई 2025 | कुल पृष्ठ – 36+4

2161 करोड़ शराब घोटाला चैतन्य की गिरफ्तारी, गरमाई सियासत

हरेली में डिजिटल यंत्रों का पूजन परंपरा और तकनीक का संगम

साय सरकार का नक्सलवाद पर प्रहार नियद नेल्लानार से विकास की बयार

जहां डर रहिस, अब विकास हे विष्णु के संग विश्वास हे

|06|
बरसात में टापू बनते गांव, बादलखोल अभ्यारण्य की सड़क बनी मुसीबत

|11|
जशपुर राजपरिवार की विरासत संभालते शौर्य प्रताप सिंह जूदेव

|24|
छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायी सक्रियता का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय ने किया जशपुर की आवाज मासिक पत्रिका का विमोचन

सीएम विष्णुदेव साय ने
पत्रिका के विमोचन
के अवसर पर
'जशपुर की आवाज'
पत्रिका की पूरी टीम को
बधाई शुभकामनाएं देते हुए
तन्मयता के साथ
पत्रिका का अध्ययन किया।

जशपुर अंचल के पाठक जशपुर की आवाज मासिक पत्रिका पढ़ते हुए

जशपुर की आवाज पत्रिका में अपनी खबर, विज्ञापन एवं रचनाओं के लिए संपर्क करें।

योगेश थवाईत - 7000026456 | प्रशांत सहाय - 9907599002

पंजीयन संख्या – RNI : CHHHIN/25/A0341

जशपुर की आवाज

वर्ष : 01 | अंक : 03 | मूल्य – 20 /-

प्रकाशन की तिथि : 31 जुलाई, 2025

संपर्क : 9302887876,9907599002

श्रीमती अमृता सहाय
स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक

श्री प्रशांत सहाय
मुख्य संपादक

योगेश बघाईत
प्रबंध संपादक

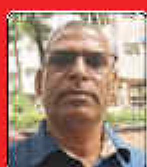

विद्यानंद ठाकुर
सह संपादक

निरंजन मोहंती
सह संपादक

शिवा मिश्रा
संभागीय प्रमुख रायपुर

परेश दास
संभागीय ब्यूरो

ऋषि बघाईत
जिला ब्यूरो जशपुर

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक

श्रीमती अमृता सहाय द्वारा
वार्ड क्रमांक 13 महाकुल बालाजी टोली,
जशपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित

आसमा पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड, जयस्तंभ चौक,
रायपुर छ.ग. से मुद्रित, मो. 9907599002

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर होगा।
पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले सम्पूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं सम्पादक की होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना

मुख्यमंत्री निवास में हरेली उत्सव

गृहग्राम बगिया में 1 लाख 108 पार्थिव शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान संपन्न

● रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रावण मास के पावन पर्व हरेली के अवसर पर राजधानी स्थित अपने निवास और गृहग्राम बगिया के फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में गौरी-गणेश, नवग्रह और भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा की गई। इस दौरान भिलाई की ग्रेजुएट धनिष्ठा शर्मा और उनके भाई दिव्य शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार कर अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई मंत्रीगण उपस्थित रहे। श्री साय ने कृषि यंत्रों की पूजा के साथ गाय और बछड़े को लोंदी खिलाकर पशुधन संरक्षण का संदेश भी दिया।

बगिया स्थित फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री ने धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ शिव पूजन कर प्रदेश के निरंतर विकास और शांति की प्रार्थना की। उन्होंने किशोरी राजकुमारी तिवारी द्वारा शिव महापुराण कथा का श्रवण किया और 1 लाख 108 पार्थिव शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान में भाग लिया।

> मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि "छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल उन्मूलन, औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए रोजगार सृजन जैसे कार्यों के लिए पूर्ण समर्पित है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए संस्कृति, पशुधन और परंपराओं से जुड़ने की अपील की।"

बस्तर में 'नियद नेल्ला नार' बनी विकास और विश्वास की नई पहचान

जहाँ बंदूकें थीं, वहाँ अब किताबें हैं – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नीति से बदल रहा बस्तर...

● रायपुर

बस्तर अब डर की नहीं, विकास की कहानी कहता है। कभी हिंसा, उपेक्षा और अलगाव का प्रतीक रहे बस्तर के सुदूर अंचलों में आज शासन की सक्रिय मौजूदगी महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू हुई 'नियद नेल्ला नार – आपका आदर्श ग्राम योजना' ने बस्तर को भय से विश्वास की ओर मोड़ा है। सुशासन का यह जीवंत मॉडल अब बदलाव की गवाही दे रहा है।

शिक्षा की रौशनी फैली जंगलों में

- 31 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति, 13 में कक्षाएँ आरंभ।
- 185 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत, 107 प्रारंभ।

स्वास्थ्य सेवा पहुँची घर-द्वार तक

- 20 उप-स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति, 16 पहले ही शुरू हो चुके।

संचार और रोशनी की नई सुबह

- 119 मोबाइल टावर की योजना में से 43 चालू।
- 144 हाईमास्ट लाइटों से 92 गाँव रौशन।

सड़क और पुलों से जोड़े जा रहे जीवन

- 173 सड़क योजनाओं में 116 स्वीकृत, 26 पूर्ण।

अब ग्रामीण ही विकास के प्रहरी

जहाँ पहले सरकारी योजना सपना लगती थी, वहाँ अब ग्रामीण स्वयं राशन, स्कूल, आंगनबाड़ी और पेंशन जैसी सुविधाओं की निगरानी कर रहे हैं। शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु बन चुका है बस्तर।

योजना से यथार्थ तक: सरकार पहुँची सबसे अंतिम व्यक्ति तक

15 फरवरी 2024 को शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य था—नक्सल प्रभावित गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना। पाँच नक्सल प्रभावित जिलों—सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर, में 54 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए, जिनके 10 किमी के दायरे में आने वाले 327 गाँवों को योजनाओं से शत-प्रतिशत जोड़ने का संकल्प लिया गया।

सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी

- 70,954 आधार कार्ड
- 46,172 आयु प्रमाण पत्र
- 11,133 मतदाता पंजीकरण
- 46,172 आयुष्मान कार्ड जारी
- 5,984 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति
- 4,677 किसानों को सम्मान निधि
- 6,460 घरों में व्यक्तिगत शौचालय
- 18,983 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन
- 30 गाँवों को डीटीएच सुविधा।

नई रोशनी की ओर मेटागुड़ा : माओवाद प्रभावित गांव में जली पहली बार बिजली

बस्तर के सुदूर और माओवाद प्रभावित क्षेत्र मेटागुड़ा गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। 27 जुलाई को जब गांव में बल्ब जला, तो यह केवल बिजली नहीं, बल्कि दशकों के अंधेरे में एक नई उम्मीद की रोशनी थी।

यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ शासन की "नियद नेल्ला नार योजना" के तहत संभव हुई, जिसके अंतर्गत 29 दिसंबर 2024 को गांव में सुरक्षा कैम्प की स्थापना हुई थी। इस कैम्प ने न केवल सुरक्षा का घेरा बनाया, बल्कि शासन और जनता के बीच की दूरी भी मिटाई।

जिला प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के समन्वय से बिजली लाइन बिछाई गई। कार्य को सफल बनाने में आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर देवेश ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण समेत अधिकारियों की सक्रिय भूमिका रही।

बिजली से अब ग्रामीणों को पढ़ाई, सिंचाई, मोबाइल चार्जिंग और संचार साधनों का लाभ मिलेगा। यह विकास की पहली सीढ़ी है, जो आने वाले समय में पूरे बस्तर के लिए प्रेरणा बनेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व ने यह सिद्ध किया है कि सुशासन केवल नीतियों से नहीं, जमीनी क्रियान्वयन व संवेदनशीलता से आता है। 'नियद नेल्ला नार' अब योजना नहीं, बस्तर की आत्मा में समाई विश्वास की लौ है।

अब बस्तर गूंज रहा है –
किताबों, योजनाओं और उम्मीदों की आवाज से।
बस्तर अब दूर नहीं, विकास की दौड़ से।

विष्णु के सुशासन में संवरता छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक 2025 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित

राज्य की आर्थिक मजबूती और भविष्य की समृद्धि की दिशा में ऐतिहासिक पहल

● रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को लेकर बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्र ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक 2025 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

यह विधेयक राज्य के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा, जिससे आने वाले वर्षों में विकास कार्यों को निरंतरता मिलेगी और राज्य वित्तीय संकट से सुरक्षित रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' संकल्प से प्रेरित-

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 तैयार किया है। इस विजन के तहत राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, और यह फंड उसी कड़ी का हिस्सा है।

क्यों जरूरी था यह फंड?

छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। वर्ष 2001-02 से लेकर 2024-25 तक खनिज राजस्व में 30 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वहीं राज्य के पूंजीगत व्यय (जैसे सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल जैसे विकास कार्यों में होने वाला खर्च) में 43 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्त मंत्री ने बताया कि पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था को तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही लाभ मिलते हैं — हर 1 रुपये के निवेश से तुरंत 2.45 रुपये का आर्थिक प्रभाव और लंबे समय में 3.14 रुपये का फायदा

ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के प्रमुख प्रावधान

- खनिज आय का 1% से 5% तक इस फंड में जाएगा
- इस फंड से केवल विकास कार्यों में निवेश होगा
- मूल राशि से विशेष परिस्थितियों में ही आहरण किया जा सकेगा और वह भी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10%
- फंड का प्रबंधन, निवेश प्रक्रिया और पारदर्शिता के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे
- इस फंड से मिलने वाले लाभांश को फिर से फंड में जोड़ा जाएगा

राज्य के लिए क्या होंगे लाभ?

- राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी
- मंदी, आपदा या आपात स्थितियों में फंड का उपयोग कर राज्य पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ेगा
- बड़े विकास कार्यों में वित्तीय मदद आसानी से उपलब्ध होगी
- निवेश के माध्यम से राज्य की आय में इजाफा होगा
- जिलेवार विकास में भी तेजी आएगी

देश में अपनी तरह की पहली पहल

ओपी चौधरी ने यह भी बताया कि इस तरह का स्थिरता फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, जिला खनिज न्यास निधि का भी बेहतर उपयोग किया जा रहा है, जिससे दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज जैसे अहम संस्थानों का निर्माण संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन मॉडल

इस विधेयक के पारित होने के बाद साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार न केवल वर्तमान की जरूरतों पर ध्यान दे रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की दिशा में सक्रियता से काम कर रही है।

डिजिटल होती शिक्षा व्यवस्था के बीच गांव के स्कूली बच्चों का अधूरापन

● योगेश बघाईत, प्रबंध संपादक (Email - news.jsp@gmail.com)

देशभर में डिजिटल क्रांति ने शिक्षा क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एआई आधारित लर्निंग टूल्स अब शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो यह तकनीकी परिवर्तन अब भी बड़े हिस्से के लिए एक अधूरा सपना बना हुआ है।

देश में डिजिटल क्रांति ने हर क्षेत्र में नई दिशा दी है—कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन... और अब शिक्षा भी इस परिवर्तन का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जब हम 'डिजिटल शिक्षा व्यवस्था' की बात करते हैं, तो एक बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है—क्या यह क्रांति वाकई गांव के बच्चों तक पहुंची है?

छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है।प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों के दूरस्थ अंचलों में आज भी बच्चे टपकती छतों के नीचे या खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और इंटरनेट इन बच्चों के लिए किसी परीकथा की तरह हैं। वे आज भी यह नहीं जानते कि 'ऑनलाइन क्लास' क्या होती है, या 'डिजिटल लर्निंग' किसे कहते हैं।

पिछली सरकारों ने अपने-अपने कार्यकाल में शिक्षा सुधार की दिशा में कुछ अहम कदम उठाए हैं। कांग्रेस शासन में प्रारंभ हुए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना ने शहरी और कुछ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल की। वहीं पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने मॉडल स्कूल की शुरुआत की, जिन्हें डीएवी संस्थान को सौंपा गया, और वे आज भी शिक्षा के बेहतर केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण भारत में आज भी डिजिटल शिक्षा एक सपना मात्र है। जर्जर भवनों, मूलभूत सुविधाओं के अभाव और तकनीकी ज्ञान से वंचित शिक्षकों के सहारे शिक्षा की गाड़ी चल रही है। जहां एक ओर महानगरों और कुछ विकसित शहरों में स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड और हाई-स्पीड इंटरनेट से युक्त स्कूल बच्चों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांवों के बच्चे आज भी टपकती छतों, बगैर बिजली और इंटरनेट के, पुराने पाठ्यपुस्तकों के सहारे भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं।

हालांकि, इस तस्वीर को बदलने के लिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,489 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें डिजिटल अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने 2025 तक 1000 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 460 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रमुख हैं। इन स्कूलों को अब ब्लॉक स्तर पर भी स्थापित किया जा रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता गांवों तक पहुंच सके।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट के तहत 5,000 से अधिक शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही, राज्य के लगभग 12 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट, ई-कॉन्टेंट और स्मार्ट लर्निंग एप्स से जोड़े जाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है।

लेकिन, इन प्रयासों के बावजूद समस्या की जड़ में अब भी बहुत कुछ बाकी है। इंटरनेट की असमान पहुंच, बिजली की अनुपलब्धता, डिजिटल साक्षरता की कमी और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, इन तमाम कारणों से डिजिटल शिक्षा का लाभ सही मायनों में गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा।

सरकार को अब नीतियों को जमीन पर लाने की आवश्यकता है। स्मार्ट स्कूल और डिजिटल क्लास केवल शहरी आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि हकीकत बनें ग्रामीण बच्चों के लिए भी। तभी यह डिजिटल क्रांति एक समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव बन सकेगी।

आज जब हम 'डिजिटल इंडिया' की बात करते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि गांव और शहर के बच्चों के बीच की डिजिटल खाई को पाटा जाए। शिक्षा केवल सुविधा नहीं, यह अधिकार है और यह अधिकार तब तक अधूरा रहेगा जब तक हर बच्चा, चाहे वह रायपुर में हो या जशपुर, बस्तर के जंगलों में, समान रूप से तकनीक-संपन्न शिक्षा प्राप्त न कर सके।

टेंडर, निर्माण, फाइलों और घोषणाओं के जंगल में गांवों के बच्चे कहीं खोते जा रहे हैं। 'डिजिटल इंडिया' का सपना, जब 'डिजिटल बेसिक सुविधाएं' ही नहीं पहुंच पा रही हों, तो यह मात्र प्रचार बन कर रह जाता है।

सरकार प्रयास कर रही है—यह सत्य है। लेकिन जरूरत केवल प्रयास की नहीं, बल्कि नियोजित और धरातलीय क्रांति की है। शिक्षकों को डिजिटल युग के अनुरूप प्रशिक्षित करना,स्कूलों में बिजली, इंटरनेट और उपकरणों की सुनिश्चित उपलब्धता और छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता का प्रसार ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।

आज समय की मांग है कि डिजिटल शिक्षा केवल शहरी अमीर बच्चों का विशेषाधिकार न रहे, बल्कि गांव के बच्चे भी यह जानें कि स्मार्ट क्लास क्या होती है, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई कैसे होती है, और ऑनलाइन शिक्षा के अवसर उनके लिए भी खुले हैं।

जब तक शिक्षा में समानता नहीं होगी, तब तक अवसरों में भी समानता नहीं आएगी। डिजिटल शिक्षा व्यवस्था तभी सफल होगी, जब हर बच्चे तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी—चाहे वह गांव की कच्ची सड़क पर बसे स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर किसी महानगर के वातानुकूलित कक्ष में।

सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई औद्योगिक नीति के साथ विकसित हो रहा छत्तीसगढ़: फार्मा सेक्टर में ऐतिहासिक कदम

● रायपुर

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देते हुए राज्य सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 19 जुलाई 2025 को नवा रायपुर के सेक्टर-05 में एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का भव्य शुभारंभ किया।

कोविड से सीखा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा प्रदेश

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोविड काल ने दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। उन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में यह बड़ी पहल हुई है। उन्होंने प्रदेश के नव निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति निवेश को प्रोत्साहित कर रही है और लाखों युवाओं को रोजगार सृजन का अवसर मिल रहा है। पिछले सात-आठ महीनों में 6 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें कई परियोजनाएं कार्यान्वयन की स्थिति में हैं।

औद्योगिक विकास में नवा रायपुर की भूमिका

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नवा रायपुर औद्योगिक निवेश और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से प्रदेश का उभरता हुआ केंद्र है। उन्होंने एस्पायर टीम की सराहना करते हुए कहा कि अनुभवी निदेशक मंडल कोमलचंद चोपड़ा, उज्ज्वल दीपक और अनिल देशलहरा — के नेतृत्व में इस यूनिट से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित होगा।

फार्मा हब बनने की ओर छत्तीसगढ़

एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स के निदेशक मंडल ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानकों से लैस यह इकाई पूरी तरह से स्वचालित और पर्यावरण-संवेदनशील है। इससे 100 से अधिक स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है और भविष्य में अनुसंधान, विकास व निर्यात के लिए भी यह केंद्र अग्रणी भूमिका निभाएगा।

विजन 2047: विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि "विकसित छत्तीसगढ़ 2047" के विजन डॉक्यूमेंट के तहत प्रदेश की GSDP को 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है, और यह जनता के सहयोग से ही संभव होगा।

सरकार की नीति से संभव हुआ औद्योगिक विस्तार

राज्य सरकार की उद्योग नीति, NRDA द्वारा भूमि आवंटन, CGMSC की नीति, SIDBI की आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा जैसे कारकों ने इस यूनिट की स्थापना को कम समय में संभव बनाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह इकाई फार्मा सेक्टर में छत्तीसगढ़ को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का कार्य करेगी।

उत्साह और विश्वास से भरा समारोह

समारोह में वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायकगण, निगम एवं आयोगों के अध्यक्षगण समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन निदेशक मंडल द्वारा अतिथियों का आभार प्रकट कर हुआ।

एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की यह शुरुआत न केवल छत्तीसगढ़ की औद्योगिक यात्रा में नया अध्याय है, बल्कि प्रदेश के युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान दे रही है। सरकार, उद्योग जगत और स्थानीय युवाओं के साझा प्रयास से छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजबूत स्तंभ बनता जा रहा है।

बरसात में टापू बनते गांव : बादलखोल अभ्यारण्य की सड़क बनी मुसीबत

ग्रामीणों के संघर्ष की कहानी...

विधायक रायमुनी भगत की पहल से तीन पंचायतों को राहत की उम्मीद...

● रिपोर्ट : निरंजन मोहंती | जशपुर/नारायणपुर

नदी-नालों पर पुल न होने से गांवों के टापू बनने की कहानियां तो सुनी ही होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सड़क की जर्जर हालत की वजह से गांव बरसात में टापू बन जाएं? यदि नहीं सुना है तो अब जान लीजिए जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के तीन पंचायतों की जर्जर सड़कों की कहानी, जो प्रतिवर्ष बारिश के दौरान ग्रामीणों के लिए एक भयंकर चुनौती बन जाती है। इन तीन पंचायतों में छुटुंग, कलिया और गायलुंगा ग्राम पंचायत शामिल हैं। ये पंचायत बादलखोल अभ्यारण्य के बीच स्थित हैं, और यहां पहुंचने का केवल एक रास्ता है एक कच्ची और खस्ताहाल सड़क।

सड़क की जर्जर हालत

साहीडांड़ से इन तीनों पंचायतों तक पहुंचने के लिए स्टेट हाइवे पर स्थित सड़क के दोनों ओर कीचड़ और गहरे गड्ढे हैं। इस सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहन, स्कूल बसें, ट्रक, और बाइक गुजरते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि कीचड़ और गड्ढों से जूझते हुए इन वाहनों का गुजरना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बरसात में यह रास्ता तालाब बन जाता है, जिससे बाइक या ऑटो कीचड़ में फंसकर गिर जाते हैं। यहां तक कि साइकिल चलाना भी कठिन हो जाता है।

सड़क के अभाव में स्वास्थ्य संकट

सड़क की जर्जर हालत का सबसे बड़ा असर स्थानीय ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बरसात के दौरान यदि किसी गांववाले को बिमारी हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीणों को हर बार कीचड़ और कीचड़ में फंसे गड्ढों से जूझना पड़ता है। यहां तक कि छात्र-छात्राएं भी इस गड्ढे वाली सड़क पर चलने के दौरान कई बार गिरकर घायल हो चुके हैं।

ग्रामीणों की पीड़ा

ग्रामीणों की परेशानियों को लेकर स्थानीय सरपंच हीरा लाल प्रधान, उप सरपंच शिव यादव और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि बादलखोल अभ्यारण्य के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हर वर्ष बरसात में इन तीनों पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे बताते हैं कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना किसी जोखिम से कम नहीं होता। इसके अलावा, इन सड़कों की बदहाली से बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी होती है।

हमेशा उपेक्षा का शिकार हुआ मार्ग

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन जर्जर सड़कों की सुध नहीं ली है। इन सड़कों की स्थिति इतनी खस्ता है कि पूरे क्षेत्र की बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस स्थिति का संज्ञान ले और इन सड़कों की मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू हो।

सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों का रुख

सड़क की मरम्मत को लेकर अधिकारियों की अनिच्छा भी साफ नजर आती है। बादलखोल अभ्यारण्य के अधिकारियों का कहना है कि उनका कार्यक्षेत्र सड़क निर्माण से संबंधित नहीं है, और वे केवल सड़क की मरम्मत का काम करते हैं। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री सड़क के अधिकारियों का कहना है कि वे सड़क बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह सड़क बादलखोल अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है, इसलिए जब तक अभ्यारण्य विभाग अनुमति नहीं देता, तब तक सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता।

क्या जीवनभर कीचड़ में जीने को मजबूर होंगे ग्रामीण?

इस जर्जर सड़क के कारण यह सवाल उठता है कि क्या बगीचा ब्लॉक के इन तीन पंचायतों के ग्रामीण जीवनभर कीचड़ भरी सड़क पर ही चलने को मजबूर होंगे? क्या इन ग्रामीणों को कभी पक्की सड़क का सपना पूरा होगा? क्षेत्र के लोग जब भी इस समस्या को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, तो उन्हें झूठे आश्वासन मिलते हैं, और जब उन्हें जवाब मिलता है तो यह कहा जाता है कि उनका क्षेत्र उनके विभाग में नहीं आता।

इस स्थिति को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? क्या उनका काम केवल आश्वासन देने तक सीमित रह गया है?

आज भी जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के सुरूंग, कलिया और गायलुंगा पंचायतों के ग्रामीणों को सड़क की जर्जर हालत से जूझते हुए जीवन यापन करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों को मिली राहत की किरण

गायलुंगा के उपसरपंच शिव यादव, सरपंच शंकर राम भगत, और शम्भु सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने विधायक को इस समस्या से अवगत कराया था। ग्रामीणों ने विधायक की सक्रियता और संवेदनशीलता की सराहना की और कहा कि 'अब जाकर कोई जनप्रतिनिधि हमारी पीड़ा को वास्तव में समझा है।'

> 'अगर जनप्रतिनिधि चाहें तो बदलाव संभव है, समस्या भी उजागर हुई, समाधान की राह भी खुली – अब नजर इस पर है कि निर्माण कार्य कितनी जल्दी शुरू होता है।'

विधायक की संवेदनशील पहल: अब बनेगा पुल

ग्रामीणों की गुहार और जशपुर की आवाज सुनकर मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक श्रीमती रायमुनी भगत स्वयं मौके पर पहुंचकर नाले के बहाव का निरीक्षण किया। उन्होंने वन मंत्री केदार कश्यप से तत्काल फोन पर बात की, और जल्द पुल निर्माण का आश्वासन प्राप्त किया।

विधायक भगत ने मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द सड़क मरम्मत के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा: 'यह वर्षों पुरानी समस्या अब और नहीं चलेगी। पुल निर्माण मेरी प्राथमिकता है। ग्रामीणों को अब और तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी।'

वन विभाग की रेस्क्यू टीम पर हाथी का हमला, वाहन क्षतिग्रस्त

अब कौन रोके हाथियों का आतंक?

● जशपुर

जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत लुड़ेग क्षेत्र में एक मादा जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। यह हाथी अपने बच्चे के साथ झुंड से बिछड़कर रिहायशी इलाके में आ पहुंची थी। भयभीत ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम पर ही हाथी ने हमला बोल दिया और स्कॉर्पियो वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

गनीमत रही कि वाहन में मौजूद चालक अनिल पैंकरा ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। रेंजर कृपा सिंधु पैंकरा सहित टीम ने नजदीकी स्कूल भवन में शरण ली। घटना के बाद हाथी कुछ समय तक क्षेत्र में उत्पात मचाता रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मादा हाथी और उसके बच्चे को रिहायशी क्षेत्र से खदेड़कर सरगुजा सीमा की ओर जंगल में भेजा। रेंजर कृपा सिंधु पैंकरा ने जानकारी दी कि दोनों हाथी फिलहाल बालाझर गांव के जंगल में मौजूद हैं और विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या

जशपुर समेत पूरे सरगुजा अंचल में मानव-हाथी द्वंद अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब हाथी रेस्क्यू टीमों पर भी हमला करने लगे हैं। बीते तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले में 220 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

स्थानीय ग्रामीण दहशत में

लुड़ेग और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब यह समस्या आम हो गई है, जिससे वे हर रात डर में जीते हैं। वन विभाग द्वारा दी जा रही सलाह और तैनात टीमें सराहनीय हैं, लेकिन ग्रामीणों का विश्वास तभी लौटेगा जब स्थायी समाधान मिलेगा।

क्या हैं भविष्य की रणनीतियाँ?

वन विभाग ने मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मशाल, सोलर फैंसिंग, मधुमक्खी ध्वनि यंत्र, और अन्य तकनीकी उपाय अपनाए हैं। ओडिशा व झारखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों से समन्वय कर संयुक्त योजना पर भी काम हो रहा है।

समस्या गहराती जा रही है, समाधान जरूरी है

यह घटना सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि गंभीर संकेत है कि अब हाथियों का खतरा सिर्फ खेतों और गांवों तक सीमित नहीं रहा। रेस्क्यू टीमें भी निशाना बन रही हैं। शासन और वन विभाग को अब तात्कालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समाधान की ओर बढ़ना होगा – वरना सवाल उठता रहेगा: 'अब कौन रोके हाथियों का आतंक?'

'देह का मोह'

वाह वाह कितना इतराता हूं मैं
इस देह को इत्र से महकाता हूं।
नख से शिख तक चमकाता हूं मैं
रंग बिरंगे पोशाकों से सजाता हूं।

संवारता हूं इसे तरह तरह से मैं
उम्र को भी छुपाता हूं।
हर मौसम से इसे बचाता हूं मैं
कुछ हो ना जाए घबराता हूं।

समय वो भी आएगा
कुछ यहां नहीं रह जाएगा
ना देह रहेगी ना रूप रहेगा
दिन दुपहरी रातें भी होंगी
हर कोई भूलता जाएगा

ये सोच सोच कर घबराता हूं मैं
फिर भी देह का मोह लगाता हूं।

– श्रीमती ममता नन्दे, जशपुर

संघर्ष से सफलता तक

युवा नेता अरविंद गुप्ता का प्रेरक सफर

● सोमेश्वर सवाईंत, प्रबंध संपादक | जशपुर

जीवन में सुसंगति हो तो सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है।आत्मिक विकास के साथ सामाजिक दायरा भी बढ़ता होता चला जाता है।सत्कर्मों की सुगंध ऐसी फैलती है कि हम स्वयं एक प्रेरणास्रोत बन जाते हैं।हिंदू कुलतिलक प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को अपना आदर्श मानने वाले युवा आदर्श के रूप में स्थापित बगीचा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता के जीवन संघर्ष की कहानी आप जशपुर की आवाज़ में पढ़ना शुरु कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के भितघरा गांव के युवा नेता अरविंद गुप्ता आज संघर्षशीलता और सामाजिक सेवा के सशक्त हस्ताक्षर बनकर युवा नेतृत्व के रूप में राजनीति को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं।जिन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर जिला व प्रदेश स्तर तक अपनी सक्रिय भागीदारी और कर्मठता से एक अलग पहचान बनाई है।

गांव के प्राथमिक विद्यालय, सर्वेश्वरी विद्या मंदिर व सरस्वती शिशु मंदिर बगीचा से अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हुए उन्होंने छात्र जीवन से ही त्याग और परिश्रम को अपना मूल मंत्र मान लिया था।पढ़ाई के साथ परचून की दुकान के संचालन से उनकी जीवन यात्रा शुरु होती है। कुछ साल किराना दुकान चलाने के बाद वे वर्ष 2003 में घर से भागकर किराए के मकान में रहने लगे और 2005 तक ट्रांसपोर्ट का काम करते रहे।वर्ष 2005 में वापस अपने गांव भितघरा पहुंचे जहां उन्होंने पहली बार ग्राम पंचायत में पंच का चुनाव लड़ा जिसके बाद यह सिलसिला बदस्तूर 2025 तक जारी रहा।इस दौरान वे दो बार निर्विरोध उपसरपंच बने और दो बार निर्वाचित उपसरपंच के पद पर आसीन रहे।

वर्ष 2025 में राजनीति ने ऐसी करवट ली कि वे एक साथ पंच और जनपद सदस्य का चुनाव लड़ते हुए जनपद उपाध्यक्ष के पद की ओर लक्ष्य बनाकर मैदान में उतर गए।किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि तीनों पदों पर उनको जीत हासिल हुई।कुदमुरा क्षेत्र क्रमांक 21 से जनपद सदस्य का चुनाव जीतकर वे जनपद पंचायत बगीचा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष बने जिसके बाद उन्होंने निर्विरोध निर्वाचित पंच पद से इस्तीफा दे दिया।

संगठन और पंचायत में सक्रिय भूमिका

- 2003 से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में संगठन और सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहे।
- 2005 से 2024 तक लगातार ग्राम पंचायत के उपसरपंच के रूप में पंचायत स्तर पर जनसेवा करते रहे।
- 2006 से 2009 तक भाजपा युवा मोर्चा मंडल मंत्री, बगीचा के रूप में युवाओं को जोड़ने का कार्य किया।
- 2010 से 2015 तक भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य, युवा मोर्चा, जशपुर रहे।
- 2016 से अब तक भाजपा युवा मोर्चा जशपुर के जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- वर्ष 2025 में जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर वे वर्तमान में जनपद पंचायत बगीचा के उपाध्यक्ष हैं।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाया

संघर्षशील नेतृत्व और सामाजिक सरोकार के साथ व्यवसायी पृष्ठभूमि से आने वाले अरविंद गुप्ता ने व्यापार के साथ-साथ समाज सेवा को भी अपनी प्राथमिकता बनाया। युवाओं के लिए रोजगार, ग्राम विकास, सामूहिक विवाह आयोजन, जरूरतमंदों की मदद, चिकित्सा शिविरों और शिक्षा सेवा में उनकी सहभागिता सराहनीय रही है।शासकीय योजनाओं में युवाओं की सहभागिता पर उन्होंने विशेष कार्य किया।

सनातन संस्कृति के संवाहक

धार्मिक आस्था,समाज सेवा के साथ उन्होंने सनातन मूल्यों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया। उनके अनुसार, "धार्मिक आस्था हमारे जीवन को संस्कारित करने का काम करती है।"उन्होंने भितघरा में सोमेश्वर महादेव की स्थापना कर भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया है जो आज बड़े जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। सोमेश्वर महादेव अब धार्मिक पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है।

जन्म और प्रारंभिक जीवन

अरविंद गुप्ता, पिता नारद गुप्ता, का जन्म 22 मई 1985 को उनके ननिहाल में हुआ।उनके परिवार में माता-पिता के अलावा तीन भाई और एक बहन हैं, जिनमें अरविंद सबसे बड़े हैं।विवाह के पश्चात, उन्होंने एक सुखी दांपत्य जीवन व्यतीत किया और उनकी एक बेटी भी है, जो उनके जीवन की प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनी हुई है। स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने गांव की पंचायत से लेकर युवा राजनीति में अपनी सेवा और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया।

राजनीति में सेवा भाव का परिचायक

जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर अरविंद गुप्ता ने राजनीति को समाजसेवा का माध्यम बनाया। उनकी संगठन क्षमता और विनम्र स्वभाव ने उन्हें जशपुर जिले में लोकप्रिय युवा नेता बना दिया है।अरविंद गुप्ता की सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात वे हमेशा विशेष पिछड़ी जनजाति कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय के बीच जाकर सबके साथ सुनते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत रहे हैं। जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरण, ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य शिविर और सामाजिक जनकल्याण कार्यक्रमों में उनकी भूमिका विशेष रही है।

संघर्षों से सीखा, चुनौतियों से जीता

अरविंद गुप्ता का सफर कभी आसान नहीं रहा। 2004 में बिना संपत्ति, आर्थिक मदद या मार्गदर्शन के निकले अरविंद ने केवल आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने दूसरों के ट्रक-पिकअप चलाए, कठिन श्रम किया और मानसिक मजबूती बनाए रखी।

ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में आने के बाद भी उन्हें किसानों से जुड़ने, व्यापार बढ़ाने और बाजार में पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक चुनौतियों का डटकर सामना किया।

राजनीति में भी बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के, उन्होंने लगातार मेहनत से पहचान बनाई। अनुभवहीनता और उपेक्षा के बावजूद वे डटे रहे और आज वे सफल उद्यमी, नेता और समाजसेवी के रूप में सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में मातृभूमि के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं।

जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पद पर बैठने के बाद उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें वे ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों के साथ सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने नवनिर्वाचित सरपंच व जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की कवायद शुरू कर दी है।

प्रेरणा का स्रोत

अरविंद गुप्ता की जीवनी बताती है कि यदि सेवा भाव, संघर्ष और संगठन क्षमता को जीवन का आधार बनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति समाज में बदलाव की मिसाल बन सकता है। उनकी राजनीतिक सक्रियता और जनसंपर्क क्षमता आज उन्हें जशपुर जिले में युवा नेतृत्व का एक प्रेरणास्रोत बनाती है।संघर्ष, सेवा और समर्पण की इस यात्रा में अरविंद गुप्ता आज भी समाज और संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं।उन्होंने राजनीति में कदम रखने वाले युवाओं के लिए एक ही सूत्र दिया है।अपने से छोटों को स्नेह दें और बड़ों को सम्मान देते हुए उनसे सलाह लें।

खेत में बीड़ा उखाड़ने पहुंची जशपुर विधायक रायमुनी भगत कृषि कार्यों में भी निभा रहीं अहम भूमिका

● जशपुर

अपने जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों के साथ-साथ मिट्टी से जुड़ाव को जीवन का मूल आधार मानने वाली जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। रोपा लगाने से पहले उन्होंने अपने खेत में पहुंचकर धान का बीड़ा स्वयं उखाड़ा और पारिवारिक कृषि कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई।

श्रीमती भगत का मानना है कि व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'जिस मिट्टी में हम पले-बढ़े, जहां से हमें अन्न, जल और वायु मिलता है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।"

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वे अपने खेतों में धान की खेती कर रही हैं और बीड़ा रोपने का कार्य वे खुद अपने हाथों से करती हैं। उनके इस जमीनी जुड़ाव को देखकर स्थानीय ग्रामीणों में भी उत्साह देखने को मिला।

विधायक श्रीमती भगत का यह व्यवहार दर्शाता है कि राजनीति और कृषि दोनों क्षेत्रों में समर्पण के साथ कार्य किया जा सकता है। उनका यह प्रयास युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करता है कि वे आधुनिक जीवनशैली के साथ अपने पारंपरिक मूल्यों और ग्रामीण संस्कृति से जुड़े रहें।

छत्तीसगढ़ का गौरव

उरांव समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमिका

● प्रशांत सहाय, मुख्य संपादक | जशपुर

छत्तीसगढ़ के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बसे जशपुर जिले की पहचान उरांव बहुल जनसंख्या के कारण विशेष है। जशपुर विधानसभा क्षेत्र में उरांव समाज का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव गहराई से जुड़ा है।

इतिहासकार मानते हैं कि उरांव जनजाति की मूल भूमि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में थी, जहाँ से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के चलते उनका पलायन हुआ। यात्रा के क्रम में वे बिहार के रोहतासगढ़ किले तक पहुँचे और वहां से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के कई हिस्सों में फैल गए।

जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर आदि छत्तीसगढ़ के जिलों में इनकी घनी उपस्थिति है। उनका सामाजिक जीवन वनवासीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा रहा है और समय के साथ इनकी सांस्कृतिक विरासत ने इन्हें एकजुट किया।

उरांव समाज के पुरोधा पुरुष

उरांव समाज में समय-समय पर ऐसे नेता और समाजसेवी सामने आए जिन्होंने समाज को दिशा दी —

माननीय गणेश राम भगत – जशपुर के लोकप्रिय नेता, विधायक, मंत्री एवं जनसेवक रहे, जिन्होंने उरांव समाज को राज्य की मुख्यधारा में लाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।वर्तमान में वे अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में पूरे देश में आदिवासी समाज को एकजुट करते हुए धर्मांतरण,नक्सलवाद, डीलिस्टिंग की मांग के साथ समाज के हितों की रक्षा का कार्य कर रहे हैं।

विक्रम भगत – जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड के ग्राम ओरंगेला से चार बार विधायक निर्वाचित हुए। समाज सेवा और राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई।

विनय भगत – वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट से जशपुर विधायक चुने गए, समाज और संस्कृति से जुड़े विषयों में सक्रिय भूमिका निभाई।

श्रीमती रायमुनी भगत – जिला पंचायत सदस्य के रूप में समाजसेवा में जुड़ी रहीं। महिलाओं के सशक्तिकरण और आदिवासी अधिकारों के लिए कार्य किया।वर्तमान में जशपुर की विधायक के रूप में जनता की सेवा में लगी हैं।

उमेश राम प्रधान –प्रदेश अध्यक्ष

समाज को संगठित करने, सामाजिक समस्याओं को दूर करने और छत्तीसगढ़ में उरांव समाज की एकजुटता को मजबूती देने वाले प्रमुख सामाजिक नेता।

सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी

उरांव समाज का राजनीति में हमेशा मजबूत दखल रहा है। पंचायती राज से लेकर विधान सभा और लोकसभा तक उरांव समाज ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।

ये समाज आज भी अपने नेतृत्व क्षमता, संघर्षशीलता और सामाजिक कार्यों के लिए पहचाना जाता है।

राजनीति के साथ-साथ सामाजिक आंदोलनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनकी सक्रियता ने समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन

■ **उरांव समाज के प्रमुख पर्व एवं परंपराएं –**

करमा पर्व – उरांव समाज का सबसे प्रमुख पर्व, जो एकता, प्रेम और प्रकृति पूजन का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति की कथा रोहतासगढ़ से जुड़ी है।जशपुर अंचल में करम वृक्ष की पूजा की जाती है।

सरहुल पर्व – चैत्र माह में प्रकृति पूजन एवं समाज में भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।जिसमें पारंपरिक वेशभूषा के साथ उरांव समाज के लोग सरना स्थल में एकत्रित होकर प्रकृति पूजन पश्चात अखरा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य कर नव वर्ष का अभिवादन करते हैं।

■ **भाषाई और सांस्कृतिक विविधता –**

कुड़ुख – उरांव समाज की मातृभाषा है। हालांकि अब हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग बढ़ा है। जशपुर इलाके में सादरी एवं कुड़ुख का प्रयोग होता है।

गोत्र व्यवस्था– उरांव समाज में 14 गोत्र मान्य हैं। गोत्र से जुड़े पेड़, पशु-पक्षी की रक्षा धार्मिक कर्तव्य माना जाता है।

विवाह परंपरा– बाल विवाह वर्जित है।सामाजिक नियमों के अनुसार ही विवाह की अनुमति दी जाती है।

खान-पान– मुख्य आहार में चावल, मड़ुआ, मांड, हंडी, मांसाहार का प्रमुख स्थान है। पारंपरिक भोजनों के साथ प्राकृतिक संसाधनों से बनी पेय सामग्रियों का उपयोग होता है।

पूजा-पद्धति

महादेव-शिव एवं पार्वती की पूजा महत्वपूर्ण है।

अखरा – सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र का स्थल। नृत्य, गीत, पूजा और सामूहिक आयोजन में विशेष महत्व।

सामाजिक चुनौतियां और धर्मांतरण

उरांव समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती धर्मांतरण की रही है।सरगुजा-संभाग में यह समस्या गंभीर है, जिससे समाज की एकजुटता पर असर पड़ रहा है।

हालांकि सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों के प्रयासों से इस पर अंकुश लगाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं।

उरांव समाज — वर्तमान संदर्भ में

उरांव समाज अपने सामाजिक मूल्यों, पारंपरिक धरोहर और संघर्षशील इतिहास के साथ आज भी छत्तीसगढ़ और देश में एक जीवंत समुदाय के रूप में जाना जाता है। इनकी सामाजिक संरचना, राजनीतिक भागीदारी और सांस्कृतिक जीवन पद्धति से नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिल रही है। उरांव समाज ने यह सिद्ध किया है कि अगर समाज संगठित हो, अपने मूल्यों को सहेजकर चले तो हर कठिनाई से संघर्ष कर अपनी पहचान बनाई जा सकती है। उरांव समाज संघर्ष, सेवा और संस्कृति का ऐसा संगम है जिसने छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी राजनीतिक जागरूकता, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक चेतना उन्हें आने वाले समय में भी नेतृत्वकारी भूमिका में बनाए रखेगी।फिलहाल छत्तीसगढ़ स्तर पर अब तक शासन में उरांव समाज को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है आने वाले समय में इस दिशा में समाज का प्रयास होगा कि उरांव समाज को भी प्रदेश में नेतृत्व का अवसर मिले।

जशपुर राजपरिवार की विरासत संभालते शौर्य प्रताप सिंह जूदेव

युवानेता से जननेता बनने की कहानी

● प्रशांत सहाय, मुख्य संपादक | जशपुर

छत्तीसगढ़ की सुरम्य पहाड़ियों, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास से समृद्ध जशपुर, जहां राजघराने की गूंज सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनसेवा और सामाजिक नेतृत्व की मिसाल भी बनी। इसी गौरवमयी परंपरा को नई पीढ़ी में आगे बढ़ा रहे हैं शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, जिनका नाम अब सिर्फ जशपुर नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में युवा जोश और जनसेवा के प्रतीक के रूप में उभर रहा है।

जशपुर राजघराने के पुरोधा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. दिलीप सिंह जूदेव ने जिस घर वापसी आंदोलन से जनमानस में गहरी छाप छोड़ी, उसी विरासत को आगे बढ़ाया उनके ज्येष्ठ पुत्र स्व. शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव ने, जिन्हें लोग युवा हृदय सम्राट कहा करते थे। अब उसी परंपरा की तीसरी पीढ़ी से राजनीति में प्रवेश कर रहे शौर्य प्रताप सिंह जूदेव अपने दृढ़ संकल्प, सहज व्यवहार और मिलनसार व्यक्तित्व से लोगों के दिलों में स्थान बना रहे हैं।

संघर्ष से बना आत्मविश्वास

25 जून 2003 को जन्मे शौर्य प्रताप सिंह जूदेव के जीवन में बेहद कम उम्र में ही गहरे आघात आए। पिता शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव का निधन तब हुआ जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, कुछ ही समय बाद दादा दिलीप सिंह जूदेव भी दुनिया से विदा हो गए। 2021 में चाचा युद्धवीर सिंह जूदेव का असमय निधन हुआ। इन दुखद घटनाओं ने उन्हें समय से पहले परिपक्व बना दिया।

परिवार की विरासत को थामने का संकल्प लेते हुए, शौर्य ने मां प्रियंवदा सिंह जूदेव और चाचा प्रबल प्रताप सिंह जूदेव व परिवारजनों के संरक्षण में राजनीति के गुर सीखे और 2021 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से सक्रिय राजनीति में कदम रखा।

युवानेता की मजबूत दस्तक

जुलाई 2021 में भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष और फरवरी 2023 में जिलाध्यक्ष बनने के बाद, शौर्य ने जिले की राजनीति में अपने तेवर और सक्रियता से कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। फरवरी 2025 में जिला पंचायत चुनाव में क्षेत्र क्रमांक 6 से प्रचंड जीत दर्ज कर जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए और फिर निर्विरोध उपाध्यक्ष बने।

प्रदेश के सबसे कम उम्र के जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने का गौरव हासिल करने वाले शौर्य प्रताप सिंह जूदेव अब जनसरोकार और विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। उनका कार्यक्षेत्र सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव में जनसंपर्क और जनता से सीधा संवाद उनकी कार्यशैली की पहचान बन चुकी है।

राजनीतिक विरासत का जिम्मेदार उत्तराधिकारी

शौर्य का स्पष्ट मानना है कि 'मेरे पिता, दादा और चाचा ने जनता की सेवा को धर्म माना था, मैं भी उसी पथ पर चलते हुए जनहित को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा।'

उनके नेतृत्व में जिला पंचायत जशपुर में विकास कार्यों की निगरानी, प्रशासन से समन्वय और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर है। वे अपने क्षेत्र दुलदुला में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता से जुड़े रहना और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना मुख्य कर्तव्य मानते हैं।

परिवार से मिली प्रेरणा, जनता से मिला विश्वास

शौर्य प्रताप सिंह जूदेव के राजनीतिक सफर में उनका परिवार हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। मां प्रियंवदा सिंह जूदेव का संबल, चाचा प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और चाची बिना सिंह जूदेव, संयोगिता सिंह जूदेव का मार्गदर्शन उन्हें लगातार नई ऊर्जा देता है। वे कहते हैं — 'दादा, पिता और चाचा के सपनों को साकार करना ही मेरा उद्देश्य है। जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें अपनाया था, उसी विश्वास को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है।'

विरासत में मिली सेवा भावना

आज जब राजनीति में वंशवाद की आलोचना होती है, तब शौर्य प्रताप सिंह जूदेव इसका अपवाद बनकर उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने विरासत को सत्ता की सीढ़ी नहीं, जनसेवा का माध्यम बनाया है।

निश्चय और नये संकल्पों के साथ बढ़ रहे शौर्य

जशपुर राजघराने की विरासत को संभालते हुए शौर्य का अगला लक्ष्य है — जनहित में प्रभावी नेतृत्व और जिले के विकास में भागीदारी। युवा शक्ति, संगठन क्षमता और सहज नेतृत्व शैली के साथ शौर्य प्रताप सिंह जूदेव का यह सफर जशपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है शौर्य सतत अपने बढ़ते राजनीतिक कद के साथ केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर मूर्त रुप देने के लिए कटिबद्ध नजर आ रहे हैं।

"शौर्य प्रताप सिंह जूदेव"
नाम नहीं, जनसेवा का वादा
जशपुर राजपरिवार से राजनीति के रण में उगता युवा सितारा...

भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार राय के नेतृत्व में 50 श्रद्धालुओं का भव्य जत्था पहुँचा बाबा धाम

भक्ति, सेवा और सामाजिक एकता का अनुपम संगम बनी पदयात्रा

● प्रशांत सहाय, मुख्य संपादक

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का एक विशाल जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के पावन दर्शन व जलाभिषेक के लिए भक्ति और उल्लास के वातावरण में पदयात्रा पर रवाना हुआ।

करीब 50 श्रद्धालुओं के इस धार्मिक काफिले ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर न सिर्फ बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की, बल्कि रास्ते भर विभिन्न मंदिरों में दर्शन-पूजन कर यात्रा को आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर कर दिया। इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि सामाजिक एकता, सेवा भावना, और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश भी था।

कृष्ण कुमार राय का संदेश 'यात्रा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है'

'बाबा धाम की यह यात्रा हमें आत्मिक शांति ही नहीं देती, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ती है। साथ चल रहे सभी श्रद्धालुओं की श्रद्धा, अनुशासन और सेवा भाव वंदनीय है। हम सब मिलकर जिस तरह भक्ति और सहयोग की भावना से इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, वह समाज में नई ऊर्जा का संचार करता है।'

बाबा से सबके कल्याण की कामना

सभी श्रद्धालु सुरक्षित एवं सकुशल बाबा धाम पहुंचे, जहां जलाभिषेक कर उन्होंने अपने और समाज के कल्याण की कामना की। इस पदयात्रा ने श्रद्धा, सेवा, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आने वाले समय में अन्य धार्मिक और सामाजिक अभियानों के लिए प्रेरणा बनेगा।

पदयात्रा में सेवा और समर्पण का भाव

यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं ने स्वच्छता, सहयोग और सेवा के आदर्शों को अपनाते हुए समाज में सद्भाव का संदेश दिया। जगह-जगह स्थानीय जनसमुदाय ने उनका आत्मीय स्वागत किया और जलपान एवं विश्राम की व्यवस्था भी की गई।

पदयात्रा में प्रमुख पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता रहे साथ

इस पदयात्रा में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण व सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। प्रमुख रूप से शामिल श्रद्धालुओं में सत्येंद्र सिंह (जिला उपाध्यक्ष), बबलू मिश्रा, अभय सोनी, आलोक राय, सुनील सोनी, सतीश जायसवाल, कनक चंद्रमिश्र, सुनील अग्रवाल, दीपक चौहान, अमरकांत वर्मा, संजय सिन्हा, संजय जैन, आशुतोष राय, संजय सोनी, विजय सोनी, कमलेश सिन्हा, देवेन्द्र गुप्ता, ललित सिंह, संजय गुप्ता, रवि मिश्रा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पत्थलगांव विधानसभा के कोतबा क्षेत्र को मिली स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐतिहासिक सौगात

विधायक गोमती साय की पहल पर 50 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के लिए 4.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति

● जशपुर / कोतबा

कोतबा क्षेत्र की जनता के लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती गोमती साय की सतत् पहल, संघर्ष और जनहितकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप शासन ने कोतबा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के उन्नयन हेतु 4 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति से अब कोतबा का स्वास्थ्य केंद्र 50 बेड की क्षमता वाले उच्च स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा,जिससे न केवल कोतबा बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी।

कोतबा को क्या मिलेंगे नए लाभ?

विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति —
जिससे अब जटिल बीमारियों का उपचार कोतबा में ही संभव हो सकेगा।

आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित केंद्र —
प्राथमिक उपचार से लेकर गंभीर बीमारियों की जांच व इलाज तक की सुविधा।

इमरजेंसी सेवाओं में सुधार —
गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज मिलेगा, जिससे जान बचाने के मौके बढ़ेंगे।

रेफर मामलों में कमी —
भर्ती क्षमता बढ़ने से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजने की आवश्यकता कम होगी।

आसपास के ग्रामीण इलाकों को लाभ —
कोतबा क्षेत्र के साथ ही सुदूर ग्रामीण अंचलों की जनता को भी चिकित्सा सुविधा का फायदा मिलेगा।

प्रतीकात्मक चित्र

जनता की आवाज बनीं विधायक गोमती साय

कोतबा क्षेत्र की सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं लंबे समय से चिंता का विषय रहीं। साधारण बीमारियों से लेकर गंभीर चिकित्सकीय आपात स्थितियों में भी क्षेत्रवासियों को जशपुर, रायगढ़ अथवा अन्य दूरस्थ शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता था। इस जमीनी हकीकत को समझते हुए विधायक गोमती साय ने इस मुद्दे को विधानसभा सत्रों में कई बार जोरदार तरीके से उठाया। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर शासन के उच्चाधिकारियों तक उन्होंने निरंतर पत्राचार और बातें कीं।

विधायक साय के निरंतर प्रयासों और क्षेत्रीय जनता के समर्थन ने आखिरकार रंग लाया, और शासन ने स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन को मंजूरी दे दी।

विधायक गोमती साय का जनता के प्रति संकल्प

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए विधायक गोमती साय ने कहा — 'यह केवल एक स्वीकृति नहीं, बल्कि कोतबा क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी आशा और अपेक्षा की पूर्ति है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और जनता को जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। यह कदम हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य मानकों को नई ऊंचाई देगा।'

विधायक श्रीमती गोमती साय ने कोतबा क्षेत्रवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी और विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में भी जनता के हितों और आवश्यकताओं के लिए सदैव तत्पर रहेंगी।

प्रतीकात्मक चित्र

जशपुर को तीरंदाज़ी अकादमी की सौगात
सी एम ने दी 20.53 करोड़ की स्वीकृति

विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को मिलेगा खेल प्रशिक्षण का नया मंच

● जशपुर

खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और आदिवासी अंचलों को खेल संरचना से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत सना तहसील के पंडरा पाठ में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए 20 करोड़ 53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि एनटीपीसी द्वारा सीएसआर मद से उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तीरंदाजी अकादमी से विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा व अन्य आदिवासी अंचलों के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपनी खेल प्रतिभा को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकें।

बहुआयामी सुविधा केंद्र बनेगी यह अकादमी पंडरा पाठ में प्रस्तावित यह अकादमी केवल एक खेल प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास का भी माध्यम बनेगी। इसमें निम्नलिखित सुविधाएँ विकसित की जाएंगी-

- मानक स्तर का तीरंदाजी खेल मैदान, बच्चों के लिए लघु पुस्तकालय
- प्राथमिक चिकित्सा एवं मेडिकल सुविधा, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र
- नर्सरी एवं हर्बल चाय की खेती हेतु विशेष क्षेत्र

> मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत बच्चों को भी वे सभी संसाधन मिलें, जो उनके भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण का भी माध्यम है।"

इस खेल में एकाग्रता, संतुलन और शरीर की स्थिरता अत्यंत आवश्यक होती है। भारत में धनुर्विद्या का गौरवशाली इतिहास है – रामायण और महाभारत से लेकर आज के आधुनिक खेलों तक। आज भी दीपिका कुमारी, अतनु दास जैसे खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन किया है।

खेल में विकास की नई उड़ान

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल खेल संस्कृति को सशक्त करेगी, बल्कि आदिवासी युवाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह अकादमी आने वाले वर्षों में जशपुर को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान दिला सकती है।

तीरंदाजीः परंपरा से प्रतिभा तक

तीरंदाजी केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक प्राचीन कला भी है। इसमें धनुष और बाण के माध्यम से लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया जाता है।

धनुषः लचीली संरचना जो बाण को छोड़े जाने में सहायक होती है।

बाणः नुकीला तीर जो लक्ष्य को भेदता है।

लक्ष्यः गोल आकृति जिसमें विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्र होते हैं।

जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत के नेतृत्व में जिला स्तरीय सुशासन शिविर संपन्न

● जशपुर / बगीचा

राज्य सरकार द्वारा सुशासन की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रोकड़ा में जिला स्तरीय सुशासन शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर की मुख्य अतिथि जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत रहीं, जिन्होंने हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ वितरित किए और शिविर को संबोधित करते हुए सरकार की लोककल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को साझा किया।

इस शिविर का आयोजन 06 ग्राम पंचायतों -देवबाड़, गम्हरिया, सोनगेरसा, सारूडीह, रोकड़ा, महादेवजबला के लिए किया गया था, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में विभिन्न विभागों के 20 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें लोक स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्यानिकी, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, पशुपालन, रेशम, विद्युत, शिक्षा, आदिवासी विकास आदि शामिल थे।

विधायक रायमुनी भगत ने दी योजनाओं की जानकारी

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और लाभ भी वितरित किया। उन्होंने हितग्राहियों को राशन कार्ड, पेंशन आदेश, बीज, खाद, पौध, मछली पकड़ने के जाल और आइस बॉक्स जैसी सामग्री सौंपी।

शिविर में विशेष रूप से सहायक आयुक्त श्री संजय सिंह ने 'धरती आबा योजना' के अंतर्गत 17 मंत्रालयों और 25 गतिविधियों की जानकारी दी और प्रधानमंत्री आवास योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल दिया।

इस अवसर पर आयोजित "गोद भराई" कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत स्कूल परिसर में पौधारोपण कर विधायक ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

> विधायक श्रीमती भगत ने कहा– "मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुशासन शिविर का उद्देश्य यही है कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ उनकी समस्याओं का समाधान गांव में ही उपलब्ध हो।"

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य गेंदबिहारी, जनपद अध्यक्ष गायत्री नागेश, उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, एसडीएम प्रदीप राठिया, जनपद सीईओ श्री श्रीवास, भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर गुप्ता, जिला महामंत्री मुकेश शर्मा, सुरेश जैन सहित बड़ी संख्या में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीणजन मौजूद रहे।

शिविर के माध्यम से शासन-प्रशासन ने जनता के द्वार तक पहुंच कर उन्हें राहत देने का प्रयास किया। विधायक श्रीमती रायमुनी भगत की सक्रिय भागीदारी और जनसमर्पित संवाद शैली ने ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। यह शिविर न सिर्फ योजनाओं का वितरण मंच बना, बल्कि विश्वास और सेवा का माध्यम भी साबित हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना से जीवन में लौटी मुस्कान,

फरसाबहार से सीधी रिपोर्ट

महत्वपूर्ण आँकड़े
जनपद पंचायत फरसाबहार से

- स्वीकृत आवास राशि : 1.2 लाख प्रति लाभार्थी
- 85 दिन मनरेगा मजदूरी के रूप में अतिरिक्त सहायता
- बिजली, शौचालय और गैस कनेक्शन की समुचित व्यवस्था
- 2024-25 में रिकॉर्ड संख्या में आवास निर्माण की स्वीकृति

● श्रीमती अमृता सहाय, संपादक | जशपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जशपुर जिले के दूरस्थ पंचायतों में जीवन की तस्वीर बदल रही है। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से अब तक लाखों परिवारों को अपना पक्का घर मिलने का सपना साकार हो चुका है। जनपद पंचायत फरसाबहार के ग्राम पंचायत बामूसाजबहार और अंकीरा के दो अलग-अलग मामलों से यह स्पष्ट होता है कि कैसे यह योजना ग्रामीणों के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान ला रही है।

बामूसाजबहार के हितग्राही श्री राम का अनुभव- 2024-25 में इस योजना के तहत 1,20,000 की राशि, 85 दिनों की मनरेगा मजदूरी, और 0.00 स्वयं का लागत में उन्हें पक्का घर मिला है। परिवार में 5 सदस्य, बिजली, गैस और शौचालय जैसी सुविधाएं अब उनके जीवन का हिस्सा हैं।

श्री राम बताते हैं - 'पहले हमारा घर कच्चा था, बारिश में पानी टपकता था, दीवारें गिरने का डर था। लेकिन अब पक्का घर मिल गया है, जिससे पूरे परिवार को सुरक्षा का अनुभव हो रहा है। अब बच्चों को पढ़ने का भी अच्छा माहौल मिल गया है।"

अंकीरा की हितग्राही श्रीमती इन्दु कालो की कहानी - श्रीमती इन्दु कालो, जिनका मुख्य आय स्रोत कृषि है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने पूरे परिवार के साथ पक्के घर में रह रही हैं। परिवार में 5 सदस्य (पति-पत्नी, 3 संतान) के साथ वे पहले टीन के घर में रहती थीं।

वे कहती हैं - 'बरसात में छत से पानी गिरता था, बच्चे भीग जाते थे, पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। अब जब सरकार ने यह घर दिया है, तो मन से भी सुकून है और समाज में सम्मान भी।"

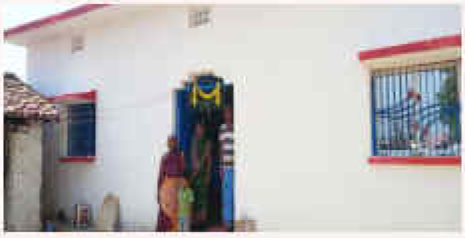

सरकार की योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन

डबल इंजन की सरकार की गारंटी के अनुरूप, अब ऐसे हजारों परिवारों का जीवन बदल रहा है, जो वर्षों से कच्चे घरों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना से अब तक 4915 हितग्राहियों को जोड़ने का कार्य हो चुका है, जिसमें 1897 पक्के मकान बनकर तैयार हो गए हैं और बाकी जल्द पूर्ण होने की स्थिति में हैं।

इस योजना ने न सिर्फ मकान दिए हैं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को भी मजबूती दी है।

यह बदलाव सिर्फ घर का नहीं,
जीवन की सोच का है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की नींव बन चुकी है।

हरेली में डिजिटल यंत्रों का पूजन परंपरा और तकनीक का संगम

● बालोद

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हरेली तिहार पर इस वर्ष बालोद जिले में एक नया नवाचार देखने को मिला। परंपरागत कृषि यंत्रों के साथ-साथ ड्रोन जैसे डिजिटल कृषि उपकरणों की भी विधिवत पूजा की गई।

इस अवसर पर ड्रोन दीदी श्रीमती चित्ररेखा साहू, श्रीमती भावना साहू और सुश्री रूचि साहू ने न सिर्फ कृषि ड्रोन की पूजा की, बल्कि गुड़ के चीले का भोग भी अर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह पूजन प्रकृति और तकनीक के मेल का प्रतीक है।

ड्रोन दीदियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरेली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए आभार जताया।

प्रधानमंत्री आवास योजना से बदल रही कुनकुरी की तस्वीर

4915 हितग्राहियों को मिला लाभ, 1897 पक्के घर बनकर तैयार

● श्रीमती अमृता सहाय, संपादक | कुनकुरी

कभी बारिश में टपकती छतों और कमजोर दीवारों में डर के साए में जीने वाले कुनकुरी क्षेत्र के ग्रामीणों की जिंदगी अब बदल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मिल रहा पक्का मकान न केवल उनके जीवन की दशा बदल रहा है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँच रहा है। जनपद पंचायत कुनकुरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद सिंह के अनुसार, विकासखंड में अब तक 4915 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिनमें 1897 पक्के मकान पूर्ण होकर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं, जबकि शेष मकान निर्माणाधीन हैं और जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे।

हर घर में अब सुकून की छांव

पक्के घरों की यह नई तस्वीर न केवल परिवारों को भौतिक सुरक्षा दे रही है, बल्कि उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बना रही है। हितग्राही

परिवार बताते हैं कि पहले वे कच्चे घरों में भय के साथ जीवन बिता रहे थे – बारिश, गर्मी, जानवरों और दीवार गिरने की चिंता हमेशा बनी रहती थी। लेकिन अब उन्हें न केवल सुरक्षित छत मिली है, बल्कि बच्चों के लिए पढ़ाई का अनुकूल माहौल भी।

एक हितग्राही ने कहा – 'पहले घर में अंधेरा, सीलन और डर था। अब नया घर मिला है तो लगता है जैसे कोई सपना साकार हो गया है। रात को चैन की नींद आती है, और बच्चे भी खुश हैं।'

स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बताया – 'अब बारिश में किताबें भीगती नहीं हैं, और पढ़ाई में मन लगता है। नया घर है, तो आत्मविश्वास भी बढ़ा है।'

डबल इंजन सरकार की गारंटी हो रही पूरी

कुनकुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5210 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें पात्रता परीक्षण के बाद 4915 हितग्राहियों को योजना में शामिल किया गया। इनमें से 1355 हितग्राहियों को दूसरी किस्त और 1663 हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य की प्रगति को देखते हुए प्रशासन शीघ्र ही शेष मकानों का निर्माण पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

'अब न डर है, न परेशानी बस सुकून भरी ज़िंदगी है'

बदलती ज़िंदगी की झलक

विवरण	संख्या
कुल आवेदन	5210 आवेदन
पात्र हितग्राही	4915 हितग्राही
पूर्ण मकान	1897 मकान
दूसरी किस्त प्राप्त	1355 हितग्राही
पहली किस्त प्राप्त	1663 हितग्राही

लोगों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

योजना का लाभ पा रहे लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने 'मोदी की गारंटी' को धरातल पर साकार किया है। अब कोई खुद को उपेक्षित महसूस नहीं कर रहा, बल्कि हर व्यक्ति सरकार से जुड़ा और सुरक्षित महसूस कर रहा है।

कुनकुरी में बदल रहा है हर आंगन

यह बदलाव केवल ईंट, सीमेंट और छत का नहीं, बल्कि उम्मीद, भरोसे और सशक्त भविष्य का निर्माण है — यही है प्रधानमंत्री आवास योजना की असली सफलता।

सुशासन से संवरता जशपुर : गरीबी से गरिमा की ओर बढ़ता हर कदम एक कहानी है

सपनों से हकीकत तक : पीएम आवास योजना ने संवारी जशपुर के ग्रामीणों की ज़िंदगी

● योगेश थवाईत

जशपुर/बगीचा । छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में एक क्रांति शांत और स्थिर रूप से आकार ले रही है—रेत,ईंट, और मेहनत से बनी एक ऐसी क्रांति जो गरीबों के सपनों को उनके घर की दीवारों में बदल रही है। यह क्रांति है प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जो न केवल एक योजना है, बल्कि एक संकल्प है—हर बेघर को एक सम्मानजनक ठिकाना देने का।प्रदेश की छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्र की मोदी सरकार से समन्वय स्थापित कर हर गांव गरीब किसान मजदूर का पक्का आवास सुनिश्चित करने की दिशा में सतत कार्य कर रहे हैं।लाखों पीएम आवास की स्वीकृति के बाद अब ये जमीन पर उतरने लगे हैं।

इस योजना के ज़रिए जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के कई गांवों में बदलाव की अनगिनत कहानियाँ सामने आई हैं।रौनी, कुटमा,पंडरापाठ जैसे गांवों में इन कहानियों ने लोगों को उम्मीद और आत्मबल दिया है।

मंगरू कोरवा का एक सपना एक संकल्प

मंगरू कोरवा का जीवन कभी कच्ची झोपड़ी में कटता था। वर्ष 2023-24 में पीएम आवास योजना के तहत उन्हें जब पक्का घर मिला, तो उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास साफ झलकने लगा। मंगरू कहते हैं – 'अब लगता है मैं भी समाज का हिस्सा हूं, मेरा भी एक घर है, जिसमें सम्मान से रह सकता हूं।'

कच्ची ज़िंदगी से पक्के भरोसे तक

बगीचा जनपद के ग्राम पंचायत कुटमा में रहने वाले सांधी राम वर्षों से कमजोर, टपकती झोपड़ी में रह रहे थे। जब 2023-24 में आवास योजना का लाभ मिला, तो उनका सपना साकार हुआ। उनका मकान अब सिर्फ संरचना नहीं, बल्कि उनका आत्मगौरव बन गया है।

ग्राम कुटमा में अब तक 112 मकानों को मंजूरी मिली, जिनमें से 54 पूरे हो चुके हैं। पंचायत की सक्रियता और ग्रामीणों की भागीदारी ने इसे जन आंदोलन जैसा रूप दे दिया है।

फुलो बाई महिला सशक्तिकरण की मिसाल

फुलो बाई पंडरा पाठ निवासी जैसी आदिवासी महिला ने साबित किया कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सरकारी सहयोग और व्यक्तिगत संकल्प से उन्होंने टपकते कच्चे घर को छोड़कर आत्मसम्मान से भरा पक्का घर बना लिया।

'यह घर सिर्फ दीवार नहीं है, यह मेरा आत्मविश्वास है,' फुलो बाई भावुक होकर कहती हैं।

बुधू राम की गरीबी के खिलाफ जीत

बरसों से ग्राम पंडरापाठ के बुधू राम अपनी झोपड़ी में मानसून से जूझते रहे। लेकिन जब पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त उनके खाते में आई, तो उनके सपनों ने दीवारें लेना शुरू किया। आज उनका परिवार सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करता है।

मंगरू राम की मेहनत के साथ मिली मदद तो बन गया पक्का मकान

62 वर्षीय मंगरू राम के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं थी। रोजगार सहायक की मदद, बैंकिंग प्रक्रिया और सरकारी मदद से उन्होंने न केवल घर बनाया बल्कि समाज में सम्मान का स्थान भी प्राप्त किया।

पहाड़ू राम को अब मिली सम्मान की छत मिली

पहाड़ू राम का पुराना घर इतना जर्जर था कि बारिश में चारों तरफ पानी भर जाता। जब उन्हें योजना का लाभ मिला, तब उन्होंने न केवल घर बनाया, बल्कि अपने बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने का सपना भी पूरा किया। 'यह सिर्फ घर नहीं, यह एक नया जीवन है,' वे गर्व से कहते हैं।

जब नीति, नीयत और नागरिक साथ हों, तब होता है परिवर्तन

प्रधानमंत्री आवास योजना ने जशपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में न केवल मकान बनाए हैं, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की नींव भी रखी है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है।

जनपद CEO केके श्रीवास का संकल्प

जनपद पंचायत बगीचा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केके श्रीवास ने कहा: 'केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सतत प्रयासों से हर ग्रामीण, किसान, मजदूर और गरीब के पक्के आवास का सपना अब साकार हो रहा है।' उनका यह बयान न केवल सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि उस जमीनी मेहनत को भी सम्मान देता है, जिससे ये योजनाएं केवल कागज पर नहीं, जीवन में उतरती दिख रही हैं।

2161 करोड़ शराब घोटालाः चैतन्य बघेल गिरफ्तार

कोर्ट से जमानत नहीं मिली; छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल

● रायपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिससे साफ है कि अब तक चैतन्य बघेल को जमानत नहीं मिल सकी है।

सुबह-सवेरे ED की दबिश, विरोध में हंगामा

चैतन्य के जन्मदिवस की सुबह 6 बजे ED की तीन गाड़ियों का काफिला दुर्ग स्थित बघेल निवास पहुंचा। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद चैतन्य को गिरफ्तारी नोटिस दिखाकर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी से पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब कांग्रेस समर्थकों ने ED की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी और गाड़ियों को रोकने की कोशिश की।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग कर बैरिकेडिंग हटानी पड़ी।

ईडी का बयानः मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गयाः " चैतन्य बघेल को PMLA के अंतर्गत चल रही जांच में अवैध वित्तीय लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त पाए जाने के कारण गिरफ्तार किया गया है।"

सूत्रों की मानें तो चैतन्य का नाम महादेव सट्टा एप से जुड़ी 500 करोड़ की संदिग्ध ट्रांजैक्शन, और फर्जी कंपनियों के जरिए धनशोधन से भी जुड़ा हुआ है। अब तक की कार्रवाई में 12 से अधिक छापे, 180+ दस्तावेजी साक्ष्य, और डिजिटल डेटा जब्त किया जा चुका है।

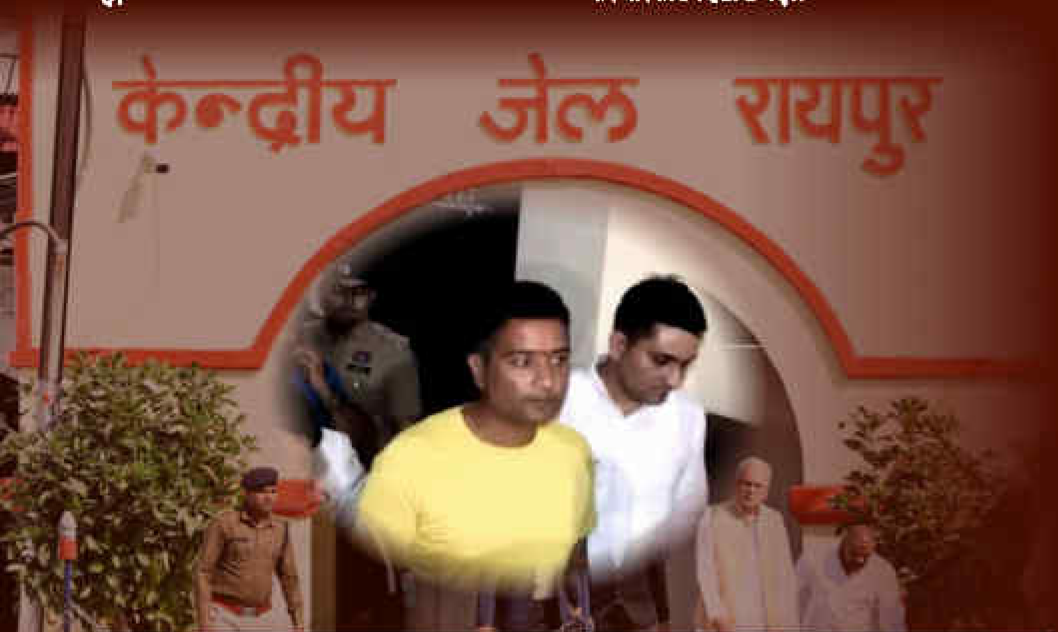

कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 4 अगस्त तक जेल

चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें 18 जुलाई को 5 दिन की ED रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद 22 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जो 4 अगस्त तक जारी रहेगी।

अब तक कोई जमानत नहीं मिली है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के PMLA मामलों में जल्दी राहत मिलना कठिन होता है, और कम से कम दो महीने तक राहत मिलने की संभावना नगण्य है।

घोटाले से जुड़ी अहम बातें

गिरफ्तारी

18 जुलाई 2025, सुबह 6 बजे

आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाला, सट्टा लिंक

रिमांड

5 दिन ईडी कस्टडी,
फिर 14 दिन न्यायिक हिरासत

जमानत स्थितिः अब तक नहीं मिली
अगली सुनवाईः 4 अगस्त 2025

भूपेश बघेल का पलटवारः यह राजनीतिक साजिश

गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा – "यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं।"

कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा का बचाव

ED की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने इसे 'तानाशाही कार्रवाई' बताते हुए प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि "जो दोषी होगा, कानून उसे छोड़ेगा नहीं।"

कांग्रेस की प्रतिक्रिया : तानाशाही, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई

भाजपा का रुख : कानून अपना काम कर रहा है।

यह गिरफ्तारी राजनीति, भ्रष्टाचार और कानून के उस चौराहे पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता छत्तीसगढ़ की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। सभी की निगाहें अब 4 अगस्त की सुनवाई और इस हाई-प्रोफाइल केस के आने वाले मोड़ों पर टिकी हुई हैं।

स्वास्थ्य विभाग की सप्लाई में टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा

मुख्यमंत्री की जीरो टोलरेंस नीति के तहत छापेमारी

● रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस नीति के तहत राज्य शासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। राज्य जीएसटी विभाग ने रायगढ़ स्थित श्याम सर्जिकल नामक फर्म पर छापेमारी कर करीब 1 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया है। यह फर्म छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में स्वास्थ्य विभाग को सर्जिकल और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करती रही है।

जांच में सामने आई चौंकाने वाली बातें –

- 48 करोड़ की आपूर्ति, जबकि वास्तविक खरीदी मात्र 10 करोड़ रुपये की।
- 4 से 5 गुना अधिक दरों पर सामग्री की आपूर्ति कर 400% से 500% तक अनुचित लाभ कमाया गया।
- टैक्स चोरी छिपाने के लिए परिवारजनों के नाम पर तीन अन्य फर्में बनाई गईं- राहुल इंटरप्राइजेस, नारायणी हेल्थकेयर, पी.आर. इंटरप्राइजेस। इन संस्थाओं के माध्यम से आपसी लेनदेन दिखाकर फर्जी बिलिंग से जीएसटी चोरी को अंजाम दिया गया।

सरकार की सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री श्री साय ने दो टूक कहा है कि सरकारी धन और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सरकारी आपूर्ति से संबंधित सभी मामलों पर सतर्क निगरानी रखी जाए। इन्हीं निर्देशों के तहत जीएसटी विभाग ने यह सशक्त कार्रवाई की है।

> सीएम विष्णुदेव साय ने कहा – "यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनता के साथ धोखा है। सरकार ऐसे सभी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।"

क्या है आगे की कार्यवाही

राज्य शासन ने इस फर्म और संबद्ध कंपनियों की सभी लेनदेन और आपूर्तियों की जांच के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में और भी आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई संभव है।

यह कार्रवाई राज्य शासन की पारदर्शिता, ईमानदारी और जनहित की प्रतिबद्धता का परिचायक है। छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार पर अब कोई समझौता नहीं करेगी।

जशपुर जिले के जिला चिकित्सालय में फर्म श्याम सर्जिकल रायगढ़ द्वारा कई करोड़ की सप्लाई कांग्रेस शासन में की जा चुकी है जिसमें जांच के बाद कार्रवाई लंबित है। इसपर भी टैक्स से जुड़े तथ्यों की जांच से कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के समेत पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आपूर्तियों की जांच भी तेज कर दी गई है।

रीपा योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर हुई कार्रवाई

तीन पंचायत सचिव निलंबित

तीन जनपद सीईओ को संभागायुक्त कावरे ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

● रायपुर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित रीपा योजना में पाई गई अनियमितताओं को लेकर शासन स्तर पर जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से विभिन्न स्तरों पर गड़बड़ी तथा निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने की पुष्टि हुई। इसी आधार पर रायपुर संभाग में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।

संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के तीन पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। इनमें महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत बिरकोनी के सचिव शंकर साहू, बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत गिर्रा के सचिव खिलेश्वर ध्रुव और जनपद पंचायत बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत लटुआ के सचिव टीकाराम निराला शामिल हैं। इन पर भंडार क्रय नियमों के उल्लंघन, बिना तकनीकी परीक्षण के मशीनें खरीदने तथा मशीनों के भुगतान को खंड-खंड कर वितरित करने जैसे आरोप हैं। इनके द्वारा कर्तव्य के प्रति बरती गई घोर लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

इसी जांच के आधार पर तत्कालीन जनपद पंचायत पलारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित नायक, जनपद पंचायत बलौदाबाजार के तत्कालीन सीईओ रवि कुमार और जनपद पंचायत महासमुंद की तत्कालीन सीईओ लिखत सुल्ताना को संभागायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों से नियत अवधि में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह कार्रवाई शासन की रीपा योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे स्पष्ट होता है कि रायपुर संभाग प्रशासन किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही को लेकर सजग है।

शिक्षा, अवसर और उन्नयन का सेतु

जशपुर का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

● श्रीमती अमृता सहाय, संपादक

व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, खेलकूद और योग का संतुलित प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, शिक्षा के साथ-साथ खेल, स्वास्थ्य और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी सोच का परिणाम है — जशपुर जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय।

ई.एम.आर.एस. की उपलब्धियाँ : शिक्षा और खेल में उत्कृष्टता के केंद्र

दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिभा संवर्धन के उद्देश्य से स्थापित ई.एम.आर.एस. संस्थान अब प्रतिभाओं के केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ खेलकूद, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, नेतृत्व विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है।

छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ उच्च सपनों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कक्षाओं, खेल शिविरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें समुचित मार्गदर्शन दिया जाता है। यही कारण है कि ई.एम.आर.एस. के छात्र NEET, IIT-JEE जैसी कठिन परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित कर रहे हैं।

खेल क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन

ई.एम.आर.एस. जशपुर के विद्यार्थियों ने कबड्डी, वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर अनेक पदक और सम्मान अर्जित किए हैं।

ई.एम.आर.एस. का दृष्टि और मिशन

छत्तीसगढ़ सरकार के आदिवासी विकास विभाग और भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित ई.एम.आर.एस. का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास, कौशल और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना है।

- शिक्षा के साथ खेल, स्वास्थ्य, संस्कार और जीवन कौशल विकास पर जोर।
- गुणवत्तापूर्ण वातावरण और संसाधनयुक्त शिक्षा व्यवस्था।
- सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण।

प्रमुख सुविधाएं

पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, गणवेश, पाठ्य-पुस्तकें।

सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई।

छात्र-छात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त अलग-अलग छात्रावास।

खेल, स्वास्थ्य, सृजनात्मक गतिविधियां एवं सांस्कृतिक मंच प्रदान करने की सुविधा।

मुख्यमंत्री की पहल: शिक्षा से बदलते जीवन

राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी अंचलों में शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम बनाया है। मुख्यमंत्री स्वयं कई बार अपने संबोधनों में यह संदेश दे चुके हैं कि — 'हमारे आदिवासी बच्चे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। उन्हें श्रेष्ठ अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल के समुचित अवसर देकर ही हम 'विकसित छत्तीसगढ़' के सपने को साकार कर सकते हैं।'

आज जशपुर जिले के छह ई.एम.आर.एस. विद्यालयों में 1860 विद्यार्थी न सिर्फ पढ़ रहे हैं, बल्कि हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विद्यालय आज शिक्षा, खेल और व्यक्तित्व विकास के समग्र केंद्र बन चुके हैं।

कलाकार की प्रतिभा को उकेरने का एक प्रयास

चित्रकार : शौर्य सहाय जशपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सौगात

जशपुर को मिले विकास के 11.52 करोड़ के पुल

जहाँ पुल बनते हैं, वहाँ विश्वास जुड़ता है और विकास दौड़ता है।

● ऋषि श्रवाईत, जशपुर ब्यूरो

जशपुर जिले की कनेक्टिविटी और ग्रामीण संरचना को मजबूती देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिलेवासियों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। उन्होंने जिले के तीन प्रमुख नदी-नालों पर उच्च स्तरीय पुलों और संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 11 करोड़ 52 लाख 43 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम जशपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

तीन इलाकों की नई पहचान

- चंपाझरिया नाला (कोडोकछार-चटकपुर मार्ग): 4.46 करोड़ की लागत से बनने वाला यह उच्च स्तरीय पुल क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ता है। बरसात में टूटने वाली सड़क की समस्या अब स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी।
- कोकिया नदी (भालूमुंडा-खजूरघाट मार्ग): 3.32 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से वर्ष भर निर्बाध आवागमन संभव होगा। ग्रामीणों को दैनिक कार्यों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में अब कोई कठिनाई नहीं आएगी।
- गुड़ा नाला (कुनकुरबाहार-तमता मार्ग, लोखरपुर के पास): 3.73 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल यातायात के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं की पहुंच को भी बेहतर बनाएगा। इससे व्यवसाय, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में गति आएगी।

ग्रामीणों को राहत, क्षेत्र को रफ्तार

इन पुलों के निर्माण से हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा। इससे न केवल जीवन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नयी दिशा मिलेगी। पुल निर्माण से वर्षा ऋतु में होने वाली परेशानी दूर होगी और आवागमन हर मौसम में संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री के प्रति जनता का आभार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जशपुर के लिए घोषित इस विकास पैकेज को लेकर स्थानीय नागरिकों में हर्ष की लहर है। ग्रामीणों ने इसे 'दीर्घकालिक विकास की बुनियाद' बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।

इन पुलों का निर्माण केवल संरचनात्मक विकास नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह स्पष्ट संदेश है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर गांव, हर नदी और हर राह को विकास से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह सौगात जशपुर के भविष्य की बुनियाद को और भी मजबूत करती नजर आ रही है।

सीएम विष्णुदेव साय की हरी झंडी से रवाना गजरथ बना बच्चों का वन्य शिक्षक

● जशपुर, ब्यूरो

जंगली हाथियों की गतिविधियों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने की दिशा में जशपुर वनमण्डल का अभिनव प्रयास – गजरथ यात्रा 2025 – लगातार सफलतापूर्वक जारी है। इस यात्रा ने अब तक फरसाबहार विकासखंड के 29 स्कूलों में पहुंचकर कक्षा 6वीं से 12वीं तक के कुल 4059 विद्यार्थियों को हाथियों के व्यवहार, उनकी गतिविधियों और मानव-हाथी संघर्ष की रोकथाम के उपायों पर जानकारी दी है।

गजरथ को मुख्यमंत्री ने किया था रवाना

गौरतलब है कि 21 जून 2025 को इस जागरूकता अभियान का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना करते हुए कहा था कि "हाथी मानव टकराव एक गंभीर समस्या है और इससे निपटने का पहला कदम है – जागरूकता।"

क्या है गजरथ यात्रा का उद्देश्य?

गजरथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य हाथी प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थियों को यह समझाना है कि हाथी कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं और उनसे किस प्रकार दूरी बनाकर सुरक्षित रहा जा सकता है। इस पहल के तहत:

- वीडियो, पोस्टर, मॉडल और इंटरएक्टिव सेशन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है।
- विद्यार्थियों को बताया जा रहा है कि हाथी से सामना होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
- वन्यजीव संरक्षण, मानव-हाथी सह-अस्तित्व और सतर्कता जैसे विषयों को सरल भाषा में समझाया जा रहा है।

शिक्षा के साथ संरक्षण का अनूठा मेल

21 जुलाई को गजरथ ने फरसाबहार के कई विद्यालयों में पहुंचकर छात्रों को न केवल जानकारी दी बल्कि जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। बच्चों ने हाथियों के व्यवहार से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिन्हें वन विभाग की टीम ने सहज व वैज्ञानिक ढंग से समझाया।

जनहित में बड़ा कदम

गजरथ अभियान को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, और अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वन विभाग इसे एक सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ा रहा है, ताकि जंगलों के किनारे बसे गांवों में संघर्ष की जगह समझ और सहअस्तित्व की भावना विकसित हो।

गजरथ यात्रा 2025 न केवल एक सूचना रथ है, बल्कि यह संवेदनशीलता, सुरक्षा और समझदारी की दिशा में बढ़ाया गया ठोस कदम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इस पहल ने साबित कर दिया है कि वन्यजीवों के साथ संतुलन बनाकर ही सतत विकास की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है।

डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में बाल अधिकार संरक्षण आयोग कर रहा सराहनीय कार्य : विष्णुदेव साय

सार्थक और रक्षक अभियान का शुभारंभ, बच्चों को अधिकारों से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल

● रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों को उनके अधिकारों से सशक्त बनाने का सराहनीय कार्य कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सार्थक व रक्षक जैसे अभिनव अभियानों की शुरुआत की गई है, जो राज्य के सुदूर अंचलों तक बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता लाने में कारगर सिद्ध होंगे।

राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री साय और अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने संयुक्त रूप से इन अभियानों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बाल अधिकारों के क्षेत्र में योगदान देने वाले पुलिस जवानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही बाल अधिकारों, मानव तस्करी और शिक्षा जैसे विषयों पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने हाल ही में पीएम श्री उमाठे स्वामी आत्मानंद विद्यालय शांति नगर रायपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में विद्यालय की जर्जर स्थिति, गंदगी, टूटे बेंच, बदबूदार शौचालय और टूटी सीढ़ियों जैसे गंभीर मामले सामने आए। बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य और विकास के अधिकारों के उल्लंघन को

देखते हुए आयोग ने प्रकरण दर्ज कर स्कूल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को नोटिस जारी किया है। अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी स्कूल प्राचार्यों से विद्यालयों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की ये पहल बच्चों को सुरक्षित और सशक्त भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।

संभाग स्तरीय युवा संसद 2025 की तैयारियों को लेकर आयुक्त महादेव कावरे ने ली महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक

कावरे ने कहा युवा संसद 2025 युवाओं में संसदीय जागरूकता बढ़ाने की पहल, 20 अगस्त से संकुल स्तर पर होगा आयोजन

● रायपुर

आयुक्त रायपुर संभाग महादेव कावरे ने आयुक्त कार्यालय में छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित युवा संसद 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली और उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की तैयारी को पूर्ण कर लिया जाए | यह युवा संसद कार्यक्रम का ब्लॉक/ विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय चयन होने के बाद संभाग स्तरीय आयोजन किया जाएगा | इसकी कार्ययोजना बना ली जाए।

इस युवा संसद 2025 का आयोजन 20 अगस्त से प्रारंभ होगा और अक्टूबर में समापन होगा। पहले संकुल स्तर उसके बाद विकासखंड स्तर में होगा।सितम्बर में जिला स्तर में होगा। अक्टूबर में यह संभाग स्तर में आयोजित होगा। इसमें स्कूल के विद्यार्थी भाग लेंगे, एक टीम में 50 सदस्य होंगे। युवा संसद को आयोजित करने का उद्देश्य युवाओं में संसदीय प्रणाली की समझ विकसित करना है।

यह युवा संसद कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छात्रों को शिक्षा एवं शासकीय कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देने का एक सशक्त माध्यम है। इस युवा संसद का आयोजन हर वर्ष किया जाता है।

बैठक में संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग रायपुर संभाग, उपायुक्त (विकास) रायपुर, उपसंचालक शिक्षा विभाग रायपुर संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि रायपुर,सहायक संचालक शिक्षा विभाग रायपुर संभाग उपस्थित रहें।

विजय प्रसाद गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव का दायित्व

● नई दिल्ली

22 जुलाई को दिल्ली में आयोजित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) की कार्यसमिति के चुनाव में जशपुर, छत्तीसगढ़ के विजय प्रसाद गुप्ता को एक बार फिर राष्ट्रीय सचिव का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।

श्री गुप्ता पूर्व में भी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनका राजनीति में लंबा अनुभव रहा है और जशपुर जैसे छोटे शहर से दिल्ली तक का उनका सफर उनके संघर्ष और समर्पण को दर्शाता है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले के वह काफी करीबी माने जाते हैं।यह नियुक्ति विजय प्रसाद गुप्ता के पार्टी के प्रति निष्ठा और उनके संगठनात्मक कौशल पर पार्टी नेतृत्व के विश्वास को पुनः स्थापित करती है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चिकित्सा प्रवेश नियमों में ऐतिहासिक सुधार

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, सुविधा और अवसरों का खुला नया द्वार

• रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों (एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.पी.टी.) में प्रवेश के लिए काउंसलिंग नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा में अधिक अवसर देना, प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करना है।

नए नियमों की मुख्य बातें

■ **बॉन्ड सेवा अवधि में राहत–** अब तक मेडिकल की पढ़ाई के बाद सरकारी सेवा में 2 साल की अनिवार्य बॉन्ड सेवा थी। सरकार ने इसे घटाकर 1 वर्ष कर दिया है, जिससे छात्रों पर बोझ कम होगा और उन्हें करियर विकल्प चुनने में अधिक सुविधा मिलेगी।

■ **ईडब्ल्यूएस सीटें अब सामान्य वर्ग को–** यदि ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की सीटें खाली रह जाती हैं तो ये अब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाएंगी। इससे सीटों की बर्बादी नहीं होगी और योग्य विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा।

■ **निजी कॉलेजों की सीटों में छत्तीसगढ़ मूल निवासी को प्राथमिकता–** निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन कोटा और एनआरआई कोटा में अगर SC, ST या OBC वर्ग की सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विद्यार्थियों को प्राथमिकता से दिया जाएगा।

■ **काउंसलिंग प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन–** अब काउंसलिंग से लेकर प्रवेश तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और छात्रों को सुविधा मिलेगी।

■ **ओबीसी आय प्रमाण पत्र में सरलता–** ओबीसी विद्यार्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे उन्हें बार-बार प्रमाण पत्र बनाने की परेशानी नहीं होगी।

■ **हर चरण में पंजीयन की सुविधा–** अब हर राउंड में विद्यार्थी अपना पंजीयन कर सकेंगे, जिससे उन्हें काउंसलिंग के हर चरण में भाग लेने का मौका मिलेगा।

कब से होगी शुरुआत?

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन नए नियमों के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 से शुरू होगी।

क्यों है यह फैसला ऐतिहासिक?

- विद्यार्थियों को मिलेगी ज्यादा सुविधा और अवसर
- प्रवेश प्रक्रिया होगी पूरी पारदर्शी और सरल
- छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा विशेष लाभ
- मेडिकल शिक्षा में आएगा नया विश्वास और उत्साह

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा - 'हमारा लक्ष्य है कि योग्य विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करें और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दें। यह सुधार राज्य के युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है।'

विद्यार्थियों के बीच शिक्षक बने महामहिम राज्यपाल रमेन डेका

• रायपुर

छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोढ़महल के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। राज्यपाल के सरल, प्रेरणादायक और आत्मीय शब्दों ने विद्यार्थियों को गहराई से प्रभावित किया।

राज्यपाल श्री डेका ने अनुशासन, समय प्रबंधन और परिश्रम को सफलता की कुंजी बताते हुए विद्यार्थियों को इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्कूल केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं बल्कि बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र है।

प्रेरक संवाद, सरल उदाहरण

राज्यपाल ने अपने संवाद को रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी.वी. रमन और 'रमन इफेक्ट' की जानकारी बेहद सरल भाषा में दी। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि भाषा कभी भी शिक्षा में बाधा नहीं बनती।

फिल्म '3 इडियट्स' का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि "हमें डिग्री के पीछे नहीं, ज्ञान के पीछे दौड़ना चाहिए। सफलता खुद-ब-खुद पीछे आएगी।"

नई शिक्षा नीति पर चर्चा

राज्यपाल श्री डेका ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह नीति विद्यार्थियों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित होता है।

टॉपर्स को मिला सम्मान, विद्यार्थियों को मिला मार्गदर्शन

अपने संबोधन में उन्होंने टॉपर्स विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर कक्षा 12वीं की छात्रा कु. दिव्या ने अपने आईएएस बनने के लक्ष्य को साझा किया, जिस पर राज्यपाल ने उन्हें UPSC परीक्षा की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण रणनीतियों और धैर्यपूर्वक प्रयास करने की सलाह दी। इसी तरह छात्रा दिव्या राजपूत को भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दिया और उत्साहवर्धन किया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायी सक्रियता का नया अध्याय

जनविश्वास विधेयक से जनता को राहत, कारोबार को सहारा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सक्रिय विधानसभा ने पारित किया ऐतिहासिक जनविश्वास विधेयक

• रायपुर

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन और जनहित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने विधानसभा की विधायी सक्रियता के माध्यम से एक बार फिर ऐतिहासिक कदम उठाया है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से जनविश्वास विधेयक 2025 पारित किया — एक ऐसा विधेयक, जो जनता को अनावश्यक आपराधिक मामलों से राहत देगा और राज्य में व्यापार, उद्योग और नागरिक जीवन को आसान बनाएगा।

अंग्रेजी शासनकाल की सख्त व्यवस्थाओं में बदलाव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा — 'यह विधेयक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम जनता को भयमुक्त और व्यापारिक जगत को विश्वास से परिपूर्ण माहौल देना चाहते हैं।'

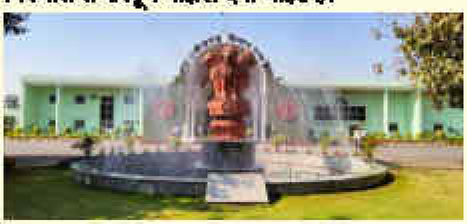

दरअसल, लंबे समय से चली आ रही ऐसी कानूनी व्यवस्थाएं, जिनमें मामूली तकनीकी त्रुटियों या विलंब के कारण आम नागरिकों और कारोबारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होते थे, उन्हें अब बदल दिया गया है।

विधेयक की प्रमुख बातें —

- 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिनमें नगरीय प्रशासन, नगर एवं ग्राम निवेश, सोसायटी पंजीयन, औद्योगिक संबंध, सहकारिता अधिनियम आदि शामिल हैं।
- छोटे तकनीकी उल्लंघनों को अब आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि प्रशासनिक आर्थिक दंड (जुर्माना) लिया जाएगा।
- अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को मिलेगा बढ़ावा।
- व्यापार और सामाजिक संस्थाओं को कानून के डर से नहीं, जिम्मेदारी से काम करने का अवसर मिलेगा।

व्यापारियों और नागरिकों के लिए क्या बदलेगा?

- नगरीय प्रशासन के तहत मकान मालिक द्वारा किराया वृद्धि की सूचना न देने पर अब आपराधिक मामला नहीं, केवल 1,000 रुपये का जुर्माना।
- सोसायटी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन में देरी पर भी मामूली आर्थिक दंड।
- महिला समूहों और सहकारी संस्थाओं को विशेष राहत — उनसे जुर्माना भी न्यूनतम रखा गया है।
- सहकारी शब्द का अनजाने में उपयोग करने पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं, बल्कि सिर्फ आर्थिक दंड।
- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में संशोधन — सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर पहली बार जुर्माना, दोहराने पर जुर्माना व कारावास।

देश में मध्यप्रदेश के बाद दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़

यह विधेयक मध्यप्रदेश के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा न केवल राजनीतिक विमर्श का मंच है, बल्कि विकास और जनकल्याण के विधायी एजेंडा की दिशा में लगातार सक्रिय है।

विधानसभा की विधायी सक्रियता — सरकार का जनमुखी चेहरा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि राज्य को सुशासन, आर्थिक स्थिरता और जनकल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने का एक मजबूत स्तंभ है।

विधानसभा सत्र के दौरान विधेयकों पर खुला संवाद, पारदर्शी प्रक्रिया और सर्वसम्मति से पारित कानून राज्य में लोकतंत्र और विधायिका की जीवंतता को दर्शाता है।

घोटालों की गठरी लेकर अब नैतिकता की बातें कर रहे भूपेश

केदार कश्यप का तीखा हमला

कोयला से लेकर बिजली तक — कांग्रेस की कथनी और करनी पर उठे सवाल

• रायपुर

छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर फिर गरमाया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 'भूपेश बघेल नैतिकता की बातें कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार घोटालों का पर्याय बन चुकी थी।"

एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में केदार कश्यप ने भूपेश बघेल पर तीखा हमला करते हुए कहा — 'छत्तीसगढ़ की जनता को अब कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क समझ आ गया है। शराब, कोयला, चावल, पीएससी, गौठान - हर क्षेत्र में घोटालों की फेहरिस्त भूपेश बघेल की सरकार के नाम दर्ज है।'

कांग्रेस की दोहरी नीति, कोल ब्लॉक से लेकर बिजली तक

केदार कश्यप ने कांग्रेस की कथनी और करनी को उजागर करते हुए कहा कि 'भूपेश बघेल ने कोयला आवंटन को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन सत्ता में रहते उन्होंने खुद राजस्थान सरकार को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस की सरकार में ही अडानी को राजस्थान में कोयला खदान संचालन का जिम्मा दिया गया।'

जनता को झूठे नारों से भ्रमित करने की कोशिश

केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के दोहरे चरित्र को जनता अब समझ चुकी है। 'जब सत्ता

में होते हैं तो सौदे करते हैं, और विपक्ष में आते ही नैतिकता का चोला पहन लेते हैं। अब जनता इनकी साजिशों को पहचान चुकी है और इन्हें सत्ता से बेदखल कर भाजपा की विकासोन्मुख सरकार को चुना है।'

वन मंत्री ने दस्तावेजों और तिथियों का हवाला देते हुए कहा –

- 16 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश भेजी।
- 19 अप्रैल 2022 को स्टेज-1 और 23 जनवरी 2023 को स्टेज-2 की वन स्वीकृति के प्रस्ताव कांग्रेस सरकार ने खुद भेजे।
- भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते खुद राजस्थान के मंत्रियों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखे, जिनका पालन करते हुए कांग्रेस ने फैसले लिए।

आर्थिक नाकेबंदी का एजेंडा, जनविरोधी साजिश

वन मंत्री ने कांग्रेस पर प्रदेश को अशांत करने की साजिश का भी आरोप लगाया – 'आर्थिक नाकेबंदी के प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस राज्य को ठप्प करना चाहती है। इससे व्यापार, रोजगार और आम जनता प्रभावित होगी। कांग्रेस का मकसद प्रदेश में अराजकता फैलाना और खुद को राजनीतिक लाभ पहुंचाना है।'

कांग्रेस को चुनौती — माफी मांगो या सच्चाई स्वीकार करो:

केदार कश्यप ने भूपेश बघेल से सवाल किया –

- क्या आप मनमोहन सरकार के दौरान लिए गए फैसलों के लिए माफी मांगेंगे?
- क्या आप और आपके नेता अपने घरों में एसी और बिजली का उपयोग बंद करेंगे?
- क्या आप जनता के सामने स्वीकार करेंगे कि आपने सत्ता में रहकर घोटालों को संरक्षण दिया?

भाजपा सरकार को मिला जनसमर्थन

केदार कश्यप ने कहा कि 'छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की झूठी राजनीति को नकारते हुए सहज, सरल और जनहितकारी नेतृत्व के रूप में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना है।'

छत्तीसगढ़ की सियासत में यह आरोप-प्रत्यारोप चुनाव बाद भी जारी है। कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के बाद आक्रामक विपक्ष की भूमिका में है, तो भाजपा अपनी सरकार को ईमानदार बताने और कांग्रेस के शासनकाल को घोटालों से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर से संघर्ष और बहस के केंद्र में ला दिया है — जहां नैतिकता बनाम भ्रष्टाचार और कथनी-करनी की बहस छत्तीसगढ़ की जनता के दरबार में है।

रायपुर उत्तर में विकास और जनसेवा का समर्पित संयोजन

विधायक पुरंदर मिश्रा की तत्परता और दूरदृष्टि

• रायपुर

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जनसमस्याओं के प्रति सजगता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण बने हैं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा। एक ओर वे बारिश के बाद क्षेत्र में उत्पन्न जलभराव जैसी तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु तुरंत सक्रिय दिखे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने क्षेत्र को दीर्घकालिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण सौगात दिलाई है।

जनता के साथ हर परिस्थिति में: जलभराव का किया स्थल निरीक्षण

हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण गायत्री नगर स्थित स्टील सिटी कॉलोनी में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसे ही यह जानकारी प्राप्त हुई, विधायक मिश्रा ने प्रातःकाल स्वयं बाइक से क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से आत्मीय संवाद कर समस्याओं को गंभीरता से सुना और तत्काल निवारण का आश्वासन दिया।

मौके पर ही नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर नालियों की सफाई का आदेश दिया गया, साथ ही नागरिकों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि – "नाली में कचरा फेंकना बंद करें – तभी नालियों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि "स्वच्छता केवल शासन या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, यह हम सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है। हम जितना अपने परिवेश को स्वच्छ रखेंगे, उतना ही बेहतर जीवन हमें मिलेगा।"

23.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

जनसेवा के साथ-साथ विकास कार्यों में भी मिश्रा ने उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास योजना के अंतर्गत 23.38 करोड़ की नगरोत्थान परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हुई है। इस स्वीकृति के अंतर्गत अधोसंरचना विकास, जलप्रदाय व्यवस्था, पाइपलाइन विस्तार तथा अत्याधुनिक PLC-SCADA प्रणाली से जल आपूर्ति सुदृढ़ किए जाने के कार्य शामिल हैं।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव का आभार प्रकट करते हुए कहा –

"जनता के आशीर्वाद और सरकार के सहयोग से हम रायपुर उत्तर विधानसभा को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। यह स्वीकृति क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी।"

सेवा, संकल्प और समाधान का नाम – पुरंदर मिश्रा

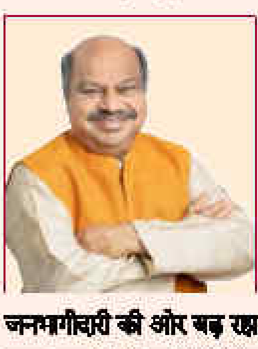

चाहे वह जलभराव जैसी समस्या हो या बहुप्रतीक्षित अधोसंरचना विकास, विधायक पुरंदर मिश्रा की सक्रियता और संवेदनशीलता हर परिस्थिति में स्पष्ट रूप से झलकती है। उनकी कार्यशैली में न केवल तत्परता है, बल्कि दूरदृष्टि और समावेशी सोच भी दिखाई देती है।

रायपुर उत्तर विधानसभा आज न केवल स्वच्छता और जनभागीदारी की ओर बढ़ रहा है, बल्कि आधुनिक नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित एक आदर्श क्षेत्र बनने की दिशा में भी निरंतर अग्रसर है – और इसके पीछे है एक सजग, सक्रिय और संवेदनशील जनप्रतिनिधि का समर्पित प्रयास।

स्टेट कैपिटल रीजनः छत्तीसगढ़ का बनेगा नया ग्रोथ इंजन

▪ जी.एस. केशरवानी, उप संचालक | सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक

● रायपुर

राजधानी रायपुर और उसके आस-पास का एरिया, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के रूप में विकसित होने जा रहा है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ इंजन बनेगा। विधानसभा में इस संबंध में विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन' ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर के क्षेत्र कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। यह पूरा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर विकसित होगा।

भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के केन्द्र में स्थित होने के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह पहल पर स्टेट कैपिटल रीजन में योजनाबद्ध और शहरी विकास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, स्टेट कैपिटल रीजन को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे राजधानी और आसपास के शहरों का प्लान्ड डेव्हलपमेंट होगा। साथ ही शहरी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण तैयार होगा। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी।

स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल शहरों में वर्ष 2031 तक 50 लाख से अधिक की आबादी रहने का अनुमान है। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव को कम करने तथा बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान रखा गया है। यह प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि के अनुरूप होगा।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के सचिव, राज्य शासन द्वारा नामित सदस्यों में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार विधायक, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निर्वाचित सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसके सदस्य संयोजक होंगे।

यह प्राधिकरण भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करेगा। वर्ष 2024-25 के बजट में स्टेट केपिटल रीजन कार्यालय की स्थापना के लिए सर्वेक्षण एवं डीपीआर बनाने के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य राजधानी और आसपास के शहरों के व्यापक विकास के लिए योजना बनाने के साथ नियामक और समन्वय संस्थान के रूप में कार्य करना है। इसके प्रमुख कार्यों में स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाना, निवेश, आर्थिक योजनाओं और इनका कार्यान्वयन, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के बीच समन्वय, आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना भी है।

प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। इसके अलावा नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग के विकास संचालक, शहरी योजनाकार, अभियंता, वित्त, संपदा, पर्यावरण नामांकित सदस्य होंगे। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में शामिल सभी जिलों के कलेक्टर इसके सदस्य होंगे।

स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राजधानी क्षेत्र विकास निधि बनाई जाएगी। इसके साथ ही एक पुनरावृत्ति निधि भी होगी। इसे राजधानी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर लगाने की शक्ति भी होगी। यह वार्षिक बजट भी तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा।

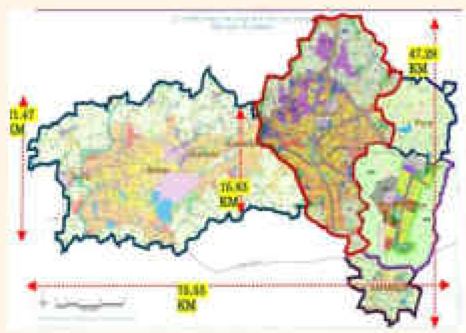

स्वाध्याय जीवन को परिपूर्ण बनाता है

पुस्तकों का अध्ययन तीन विभिन्न प्रकारों से हमारी सहायता करता है। पुस्तक हमारे एकान्त में साथियों की तरह होती है- बुढ़ापे या जीवन के शेष दिनों में भी साथियों की तरह हमें प्रसन्नता देती रहती है। दूसरी बात यह है कि पुस्तक अच्छी भाषा विकसित करने की शिक्षा देती है। भाषा को आकर्षक प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। विवाद या तर्क-वितर्क के समय इसका बड़ा व्यापक लाभ होता है क्योंकि हम अपनी बहस प्रभावशाली ढँग से नहीं कर सकते, यदि भाषा पर हमारा अचूक अधिकार नहीं है।तीसरी बात यह कि हम अपनी मानसिक शक्तियों का विकास अध्ययन के द्वारा ही कर सकते हैं और कठिन परिस्थिति आने पर शीघ्रता से उचित निर्णय भी ले पाते हैं और व्यावहारिक दुनियाँ की स्थितियों से अधिक प्रभावशाली ढँग से व्यवस्थित और नियंत्रित करते हैं। जीवन के व्यावहारिक अनुभव निस्संदेह रूप से मनुष्य की व्यावहारिक समस्याओं के बीच व्यवस्था पैदा करने में सहायक होते हैं लेकिन एक सुपठित मनुष्य बड़ा अच्छा सलाहकार होता है क्योंकि वह खूब अच्छे ढँग से योजनाएँ बनाता है और हर चीज की ठीक व्यवस्था करता है। पुस्तक पढ़ने के ये सभी लाभ हैं लेकिन अधिक पढ़ने या अधिक मात्रा में पुस्तक सेवी होना घातक है क्योंकि इससे आदमी निष्क्रिय तथा अव्यावहारिक हो जाता है। पुस्तक पढ़ने की आदत मनुष्य की जन्मजात योग्यता के विकास में सहायक होती है। पुस्तक प्रेम से ही मनुष्य की नैसर्गिक क्षमता का विकास होता है। यह कार्य इस तरह होता है जैसे पौधों के अति विकसित अंगों को छाँटने या कतरने से उनका विकास होता है। लेकिन पुस्तकों के अध्ययन के साथ जीवन के व्यावहारिक अनुभवों का मिश्रण होना अनिवार्य है, नहीं तो सभी भाव और विचार अस्पष्ट रह जाएँगे।हम लोगों को इसीलिए अध्ययन नहीं करना चाहिए कि केवल दूसरों के वक्तव्य को काटें और उनकी बात को गलत साबित करें। केवल इसलिए अध्ययन करना निरर्थक है कि पुस्तकों में जो भी छपा है वह विवादों से परे है, उसका हर तथ्य सही है। पुस्तकों में विवाद के विषयों की खोज करते रहने के लिए अध्ययन करना भी ठीक नहीं है।अगर इन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य है अच्छे और बुरे में क्या भेद है, उसे पहचाने समझने की शक्ति प्राप्त करना और वस्तुओं के वास्तविक मूल्य की खोज करना।सभी पुस्तक समान महत्व की नहीं होती। किताबें कई प्रकार की होती हैं और उनका अध्ययन भी भिन्न-भिन्न तरह से होना चाहिए। अनिश्चित मूल्यों की भी

कई पुस्तक हैं। ऐसी पुस्तकों का सम्पूर्ण अध्ययन नहीं होना चाहिए। जैसे मामूली किस्म के भोजन और पेय पदार्थ केवल स्वाद लेने के लिए होते हैं और उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से ऐसी पुस्तकों का आंशिक अध्ययन ही पर्याप्त होता है। कुछ पुस्तक उत्तम है लेकिन सर्वोत्तम नहीं कही जा सकती। जैसे कुछ खाद्य तथा पेय पदार्थ अच्छे होते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं कि धीरे-धीरे खाकर उनका स्वाद ले लेकर आनन्द लिया जा जाए।ऐसी पुस्तक साधारण तौर पर पढ़ने लायक होती हैं। उन पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं होता। ऐसी पुस्तक एक ग्रास में ही निगलने लायक होती हैं किंतु कुछ पुस्तक सर्वोत्तम कोटि की होती हैं। उनका अध्ययन धीमी गति से तथा सावधानी से ठहर ठहर कर होना चाहिए। भोजन के लिए बैठा हुआ आदमी जैसे उत्तम कोटि के खाद्य और पेय पदार्थों को कण्ठ में पहुँचने से पहले देर तक उनका आनन्द लेता है, ठीक उसी तरह से ऐसी पुस्तक आनन्द देने वाली होती है।

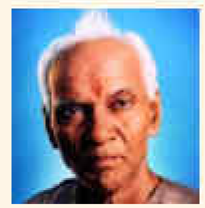

पं श्रीराम शर्मा आचार्य
युग निर्माण योजना,
अप्रैल 1971 – पृष्ठ 23

इक्कीसवीं सदी : नारी सदी

संघ प्रमुख मोहन भागवत का संदेश महिलाओं को रूढ़ियों से मिले मुक्ति

● नई दिल्ली

'राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है, उन्हें रूढ़िवादी रीति-रिवाजों और सामाजिक बेड़ियों से मुक्त करना होगा।' — राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह वक्तव्य आज के दौर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई सोच और दृष्टि का परिचायक है।

महाराष्ट्र के सोलापुर में उद्योगवर्धिनी के कार्यक्रम में भागवत ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को किसी के कृपा से नहीं, बल्कि स्वयं अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पुरुषों का यह दावा करना कि वे महिलाओं का उत्थान करेंगे — यह दृष्टिकोण ही गलत है। उन्हें अपनी राह खुद तय करने दें।

श्री भागवत ने कहा — 'ईश्वर ने महिलाओं को अतिरिक्त गुणों से नवाजा है। वे न सिर्फ पुरुषों के समान कार्य करने में सक्षम हैं, बल्कि वे उन कार्यों को भी कर सकती हैं, जो सामान्यतः पुरुष नहीं कर सकते।'

उन्होंने यह भी कहा कि महिला सिर्फ परिवार की धुरी नहीं है, वह आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणास्रोत भी है। समाज को यदि प्रगतिशील बनाना है तो महिलाओं के अधिकार, सम्मान और अवसरों को सुनिश्चित करना ही होगा।

उद्योगवर्धिनी की सराहना करते हुए भागवत ने कहा — 'जो भी संगठन महिलाओं को सशक्त बना रहा है, वह वास्तव में राष्ट्र को सशक्त बना रहा है।'

इक्कीसवीं सदी को 'नारी सदी' मानते हुए भागवत का यह उद्बोधन आज के महिला जागरण आंदोलन को नई ऊर्जा देता है। यह संदेश उन तमाम सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, जो अब तक महिलाओं को सीमाओं में बांधे हुए थीं।

आज की महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं है,वह राष्ट्र निर्माण की साथी है। उसकी मुक्ति में ही समाज की असली स्वतंत्रता और प्रगति निहित है।

राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को मिला नया संबल

छत्तीसगढ़ का परंपरागत तिहार हरेली

▪ छगन लाल लोन्हारे, उप संचालक जनसंपर्क

प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में हैं। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की इन डेढ़ साल के अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर रिकॉर्ड कायम किया है।

छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत् रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्यौहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदीकर न सिर्फ किसानों को मान बढ़ाया, बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही किसानों के खाते में रमन सरकार के पिछले दो वर्ष का बकाया धान के बोनस 3716.38 करोड़ रूपए अंतरित कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत गांवों में बसता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का व्यापार, उद्योग बढ़ेगा।

परंपरा के अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों की जिद पर अभिभावक जैसे-तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। हरेली तिहार के दिन सुबह से तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं और खेती-किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदारी, फावड़ा, गैंती को साफ कर घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने-अपने घरों में आराध्य देवी-देवताओं की साथ पूजा करते हैं। गांवों के ठाकुरदेव की पूजा की जाती है।

हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियुक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं। गांव के सहाड़ादेव अथवा ठाकुरदेव के पास यादव समाज के लोग जंगल से लाई गई जड़ी-बूटी उबाल कर किसानों को देते हैं। इसके बदले किसानों द्वारा चावल, दाल आदि उपहार में यादवों को भेंट करने की परंपरा रही है।

सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओढ़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा-भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती-किसानी का कार्य लगभग हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर, धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण किया जाता है।

हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते है। गेड़ी बांस से बनाई जाती है। दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाड़कर उन्हें दो

भागों में बांटा जाता है। उसे नारियल रस्सी से बांधकर दो पऊआ बनाया जाता है। यह पऊआ असल में पैर दान होता है जिसे लंबाई में पहले काटे गए दो बांसों में लगाई गई कील के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती हैं, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है। इसलिए किसान भाई इस दिन पशुधन आदि को नहला-धुला कर पूजा करते हैं। गेहूं आटे को गूंथ कर गोल-गोल बनाकर अरंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेटकर गोधन को औषधि खिलाते हैं। ताकि गोधन को रोगों से बचाया जा सके। गांव में पौनी-पसारी जैसे राऊत व बैगा हर घर के दरवाजे पर नीम की डाली खोंचते हैं। गांव में लोहार अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए चौखट में कील लगाते हैं। यह परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है।

पिछले के दशक में गांव में बारिश के समय कीचड़ आदि हो जाता था उस समय गेड़ी से गली का भ्रमण करने का अपना अलग ही आनन्द होता है। गांव-गांव में गली कांक्रीटीकरण से अब कीचड़ की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। हरेली के दिन गृहणियां अपने चूल्हे-चौके में कई प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है। किसान अपने खेती-किसानी के उपयोग में आने वाले औजार नांगर, कोपर, दतारी, टंगिया, बसुला, कुदारी, सब्बल, गैती आदि की पूजा कर छत्तीसगढ़ी व्यंजन गुलगुल भजिया व गुड़हा चीला का भोग लगाते हैं। इसके अलावा गेड़ी की पूजा भी की जाती है। शाम को युवा वर्ग, बच्चे गांव के गली में नारियल फेंक और गांव के मैदान में कबड्डी आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। बहु-बेटियां नए वस्त्र धारण कर सावन झूला, बिल्लस, खो-खो, फुगड़ी आदि खेल का आनंद लेती हैं।

नक्सल प्रभावित इलाकों में डिजिटल क्रांति की दस्तक

दूरसंचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर की घोषणा – अंतिम गाँव तक पहुँचेगी 4जी कनेक्टिविटी

● रायपुर

नक्सलवाद की छाया से उबरते छत्तीसगढ़ के दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में अब डिजिटल कनेक्टिविटी की नई रोशनी फैलने जा रही है। केंद्र सरकार राज्य के इन क्षेत्रों में 400 नए बीएसएनएल मोबाइल टावर लगाने जा रही है, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना अब इन इलाकों में भी साकार हो सकेगा।

यह महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने रायपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में की। बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास, डाक और दूरसंचार विभाग के अधिकारी शामिल थे।

डिजिटल सशक्तिकरण का नया अध्याय

डॉ. शेखर ने बताया कि इन टावरों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। सुरक्षा बलों और वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद, नक्सल क्षेत्रों में 4जी नेटवर्क का विस्तार तेजी से होगा। उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता है कि देश का हर नागरिक डिजिटल सेवाओं से जुड़ सके – फिर चाहे वह अंतिम गाँव में ही क्यों न रहता हो।"

ग्रामीण विकास योजनाओं की सराहना

बैठक में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया गया। इन योजनाओं से राज्य में आवासीय और बुनियादी ढांचे में बड़े परिवर्तन देखे जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ बना मॉडल राज्य

डॉ. शेखर ने स्व-सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में 'पिंक ऑटो' योजना जैसे नवाचारों से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इन ऑटो पर महिलाओं का स्वामित्व है और यह योजना अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकती है।

शिक्षा और समावेशन की दिशा में कदम

राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों के डिजिटलीकरण के प्रयासों की भी सराहना की गई। छात्रों को अब JEE, NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी में तकनीकी सहायता मिल रही है। साथ ही दिव्यांग छात्रों के

लिए भी विशेष डिजिटल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जो एक समावेशी और मानवीय पहल है।

जनकल्याण की अंतिम पंक्ति तक पहुँच

अपने संबोधन के अंत में डॉ. शेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज सरकारी योजनाएं वंचित, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुँच रही हैं। "सरकार की प्रतिबद्धता है कि डिजिटल, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को साथ लेकर 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को धरातल पर उतारा जाए।"

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए "CM IT फेलोशिप कार्यक्रम" की शुरुआत

● रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के तकनीकी दक्ष और नवाचारी युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में "CM आईटी फेलोशिप कार्यक्रम" की शुरुआत की गई है, जो युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक अनुभव का द्वार खोल रहा है।

M.Tech in AI & Data Science का मिलेगा मौका

इस योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT-NR) में Artificial Intelligence और Data Science जैसे भविष्य गामी क्षेत्रों में M.Tech करने का अवसर मिलेगा।

- सरकार देगी पूरी फीस और 50,000 प्रति माह फेलोशिप
- राज्य सरकार वहन करेगी पूरी ट्यूशन फीस
- चयनित छात्रों को मिलेगी 50,000 प्रति माह की फेलोशिप
- कोर्स की अवधि में मिलेगा ई-गवर्नेंस, हेल्थटेक, एजुटेक जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का वास्तविक अनुभव
- AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण

यह फेलोशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया मिशन और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी दक्षता पर जोर दिया गया है।

अभी करें आवेदन

प्रदेश के युवाओं से अपील है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए iiitnr.ac.in पोर्टल पर जाकर जल्द आवेदन करें।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा 'यह फेलोशिप कार्यक्रम छत्तीसगढ़ को डिजिटल युग में अग्रणी राज्य बनाएगा। युवाओं की भागीदारी ही राज्य की असली शक्ति है।"

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं की मांगों को लेकर संघ प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर और डीपीओ से की मुलाकात

शासकीय कर्मचारी का दर्जा, जीने लायक वेतन और बुनियादी सुविधाओं की मांग पर मिला आश्वासन

• श्रीमती अमृता सहाय, संपादक | जशपुर

छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ पंजी.409 की कार्यकारी प्रांताध्यक्ष, सरगुजा संभाग प्रभारी और जशपुर जिलाध्यक्ष श्रीमती कविता यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर रोहित व्यास और जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, जीने लायक वेतन, पेंशन-ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, समूह बीमा, और अनुकंपा नियुक्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की।

कार्यकारी प्रांताध्यक्ष,सरगुजा संभाग प्रभारी और जशपुर जिलाध्यक्ष श्रीमती कविता यादव ने कहा कि 50 वर्षों से कार्य कर रहीं लाखों कार्यकर्ता-सहायिकाएं आज भी न्यूनतम वेतन और अधिकारों से वंचित हैं। वर्तमान में कार्यकर्ता को मात्र 4500 और सहायिका को 2250 मानदेय मिलता है, जो बेहद कम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार होने से अब उम्मीद है कि मांगों पर गंभीरता से विचार होगा।

स्थानीय समस्याओं को लेकर भी जिलाध्यक्ष ने डीपीओ अजय शर्मा से विस्तार से चर्चा की। इनमें पोषण ट्रेकर में फेस कैप्चर की व्यावहारिक दिक्कतें, बिजली बिल, भवन मरम्मत, गैस सिलेंडर की आपूर्ति, मानदेय में देरी, और ड्रेस की खराब गुणवत्ता जैसी समस्याएं शामिल थीं। डीपीओ ने शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर प्रतिमा शर्मा, रूपा सोनी मिंज, रोसलिन, उषा यादव, सुशीला यादव, शोभन्ति पैंकरा, अनिमा, ग्लोरिया, सुनीता भाई, एलिस रजनी, सुमत्री, मीरा और कुंती सहित कई सदस्य उपस्थित रहीं।

संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

ये हैं प्रमुख मांगे

1. **नियमितीकरण :** देश मे 50 वर्ष से लागू आइसीडीएस योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रो मे कार्यरत कार्यकर्ता सहायिकाओ को भी शिक्षाकर्मी.पंचायत कर्मी.की तरह शासकीय करण की नीति बनाकर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे और कार्यकर्ता को तृतीय श्रेणी और सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जावे।
2. **जीने लायक वेतन :** शासकीय कर्मचारी घोषित होते तक पूरे देश मे एक समान वेतन कार्यकर्ता को प्रतिमाह 26000/- और सहायिका को 22100/-(कार्यकर्ता का 85%) शीघ्र लागू किया जावे।
3. **सेवा निवृत्ति पश्चात पेंशन ग्रेजुवेटी :** 35-40 वर्ष विभाग की सेवा करने के बाद भी बुढ़ापे के समय जीवन यापन हेतु ना तो कोई पेंशन मिल रहा है और ना ही एक मुस्त राशि कार्यकर्ता को 10000/और सहायिका को 8000/मासिक पेंशन और बुढ़ापे के शेष जीवन यापन के लिए कार्यकर्ता को 5 लाख रुपयेऔर सहायिका को 4 लाख रुपये एक मुस्त ग्रेजुवेटि राशि प्रदान किया जावे।
4. **समूह बीमा योजना लागू करना :** भविष्य की सुरक्षा के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओ के लिए समाजिक सुरक्षा के रूप मे सेवानिवृत्ति पर सभी कार्यकर्ता सहायिकाओ को.पेंशन.ग्रेच्युटी.समूह बीमा और कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावे।
5. **अनुकंपा नियुक्ति :** कार्यकर्ता सहायिका के आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिया जावे।
6. **महंगाई भत्ता :** विगत कुछ सालों में महंगाई मे बेतहाशा वृद्धि हुई है, वर्तमान मानदेय से घर चलाना सम्भव नहीं है इसलिए हमारे मानदेय को महंगाई भत्ता के साथ जोड़ा जाय महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय।
7. **पदोन्नति :** पदोन्नति बावत वर्षों से अल्प मानदेय में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को पदोन्नति के पद, रिक्त होने के बाद भी 50% का प्रतिबंध होने के कारण इन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है 50% का बंधन को समाप्त किया जाय और कार्यकर्ता को बिना उम्र बंधन के वरिष्ठता क्रम में बिना परीक्षा के सुपरवाइजर

के रिक्त शत प्रतिशत पद पर लिया जाय, इसी तरह सहायिकाओ को भी 50% के बंधन को समाप्त कर कार्यकर्ता के पद रिक्त होने पर शत प्रतिशत वरिष्ठता क्रम में कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति किया जाये।

8. **पोषण ट्रेकर, THR वितरण मे फेस केप्चर :** सरकार द्वारा वर्तमान मे पोषण ट्रेकर.THR वितरण मे फेस केप्चर.कार्यकर्ता सहायिकाओ के उपस्थिति का फेस केप्चर FRS और e-KYC के माध्यम से केन्द्र के सभी कार्य को डिजिटल किया गया है जिससे हितग्राहियो को और कार्यकर्ता सहायिकाओ को कई व्यवहारिक परेशानी और कठिनाईयो का सामना करनी पड़ रही है इसे बंद कर आफ लाईन सभी कार्य लिया जाये।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संघ ने किया अपील,डबल इंजन की सरकार मिलकर करे समस्या का निदान

जिलाध्यक्ष श्रीमती कविता यादव ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अपील किया है कि अब केन्द्र और छत्तीसगढ़ राज्य दोनो स्थान पर आपकी ही डबल इंजन की सरकार है,ऐसे में डबल इंजन की सरकार नारी शक्ति की पीड़ा और मन की बात को सुनते हुये हमारी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

संघ ने कही बड़ी बात

संघ के संरक्षक देवेंद्र पटेल ने कहा कि सर्व प्रथम हम भारत के नागरिक है और यहां कार्य करने वाली कार्यकर्ताएं सहायिकाएं महिला भी है। विगत 2 अक्टूबर 1975 जब से देश मे आइसीडीएस की स्थापना हुई है तब से आंगनबाड़ी केन्द्रो मे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओ के रूप मे केंद्र और राज्य सरकार को आंगनबाड़ी केन्द्रो मे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओ के द्वारा अपनी सेवाये दे रही है हर योजना को घर घर और जन जन तक पहुंचाने का काम भी इनके द्वारा ही कराया जा रहा है। लेकिन सेवायें 50 वर्ष होने के बावजूद भी इन्हें ना तो कर्मचारी का दर्जा मिल पाया है और ना ही श्रमिक मजदूर का और ना ही इन दिनो मे न्यूनतम मजदूरी,पेंशन,ग्रेज्युटी,समूह बीमा,चिकित्सा और सम्मान जैसी कोई बुनियादी सुविधा। देश के लगभग 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाये इन 50 वर्षो मे लगातार समय पर शासन का ध्यानाकर्षण करते आ रहे हैं।

दुखद बात यह है कि इन 50 वर्षो मे केन्द्र सरकार की ओर से प्रारंभिक मानदेय के रूप मे कार्यकर्ता को रू 4500/- एवं सहायिका को रू.2250/- दिया जा रहा जो न्यूनतम वेतन से काफी कम है इसे जीने लायक वेतन कदापी नहीं कहा जा सकता।इसके अलावा और कोई सुविधा ना मंहगाई भत्ता,ना पेंशन,ना ही ग्रेज्युटी,ना ही समूह बीमा,ना ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति और ना ही पदोन्नति। जब इनके द्वारा अपनी इन बुनियादी सुविधाओ की मांग की जाती है तो केन्द्र की सरकार राज्य पर राज्य की सरकार केन्द्र के कर्मचारी है कहकर पल्ला झाड़ लेते है और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है।संघ ने डबल इंजन की सरकार से सभी समस्याओं का निदान समय रहते किये जाने का अपील किया है।

छत्तीसगढ़ रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी से पंजीकृत है छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ पंजी.409

छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ एक पंजीकृत संस्था है जो 22 सितंबर 2003 को छत्तीसगढ़ रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी से पंजीकृत हुआ है,जिसका मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों व संरक्षण के लिए काम करना है।इस वक्त संघ की प्रांताध्यक्ष श्रीमती सरिता पाठक,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्रीमती कविता यादव और संरक्षक के रूप में देवेंद्र पटेल संघ के विस्तार और मजबूती पर विशेष ध्यान देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हक अधिकार व संरक्षण के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे है।समय समय पर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की है,जिसमें धरना प्रदर्शन और रैली का निकाला जाना सहित ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम शामिल रहा है।उक्त चरणबद्ध आंदोलन में संघ को अभी तक काफी सफलता मिली है,जिस कारण राज्य में सबसे ज्यादा सदस्य इस संघ में ही जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ पंजी.409 का स्थापना दिवस 22 सितंबर 2003 को मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संघ की प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करना,जीने लायक वेतन,नियमितीकरण सहित अन्य प्रमुख मांगें शामिल हैं।

ऑपरेशन आघातः जशपुर पुलिस की सख़्त कार्रवाई 89 मामलों में 92 अपराधियों पर शिकंजा

अपराधियों के विरुद्ध निर्णायक मोर्चा, नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं

● जशपुर

अपराध के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में जशपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा 'ऑपरेशन आघात' अब तक कई अपराधियों के लिए काल बन चुका है। जनवरी 2025 से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत अब तक 89 मादक पदार्थ से जुड़े मामलों में 92 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 14.37 करोड़ रुपये मूल्य का अवैध माल जब्त किया गया है।

सीमावर्ती इलाकों में सतत नाकेबंदी जांच और ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत सूचना तंत्र के कारण लगातार जशपुर पुलिस को नशे के सौदागरों की पुष्ट सूचना मिलती है और एसएसपी शशिमोहन सिंह के निर्देशन पर जशपुर पुलिस उन सौदागरों तक पहुंच कर आपरेशन आघात को अंजाम देने का काम करती है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का बयान

"ऑपरेशन आघात न केवल अपराधियों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन का मिशन है। हमारा प्रयास है कि जशपुर को नशा मुक्त और सुरक्षित जिला बनाया जाए। पुलिस केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव में जनजागरूकता और पुनर्वास की दिशा में भी काम कर रही है।"

"ऑपरेशन आघात" केवल एक पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि यह सामाजिक संकल्प, क़ानूनी रणनीति और जन सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। यह अभियान जशपुर जिले को नशे और संगठित अपराध से मुक्त करने की दिशा में एक सशक्त कदम है और इसमें आम जनता की भागीदारी भी पुलिस की सफलता का आधार बन रही है।

– शशि मोहन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जशपुर

राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा में सक्रिय हुई मंत्रिपरिषद उपसमिति

छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक आंदोलनों और जन संघर्षों से जुड़े मामलों की संवेदनशील समीक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद उपसमिति को सक्रिय भूमिका सौंपी है। इसी कड़ी में 18 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर, रायपुर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े बतौर सदस्य उपस्थित रहे।

15 प्रकरणों की समीक्षा, निष्पक्ष प्रक्रिया की पहल

बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त 15 विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। उपसमिति ने इन मामलों पर विस्तृत चर्चा के बाद उन्हें मंत्रिपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इन प्रकरणों पर मंत्रिपरिषद की अंतिम अनुशंसा के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

139 प्रकरणों की हो चुकी है समीक्षा, 126 पर मिली अनुशंसा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि अब तक मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठकों में 139 राजनीतिक आंदोलन से जुड़े मामलों को प्रस्तुत किया जा चुका है, जिनमें से 126 प्रकरणों पर मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। यह आंकड़ा राज्य सरकार की गंभीरता और संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रमाण है।

न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का संतुलन

राज्य सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन की अहम भूमिका होती है, लेकिन इससे जुड़े मामलों का निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से निराकरण किया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण भी हो सके और एक सुदृढ़ विधि व्यवस्था भी बनी रहे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का वक्तव्य

'सरकार की प्राथमिकता है कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष समीक्षा हो, ताकि विधिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक परंपराओं के बीच संतुलन कायम रह सके। मंत्रिपरिषद उपसमिति इस दिशा में निरंतर काम कर रही है।'

यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और विधिसम्मत प्रक्रिया में विश्वास को रेखांकित करती है। राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की संवेदनशील समीक्षा और उनके निराकरण की दिशा में यह कदम राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में सकारात्मक संदेश दे रहा है।

जशपुर में शुरू हुई एनसीसी एयर स्क्वाड्रन, युवाओं को मिलेगा उड़ान का अवसर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से मिली ऐतिहासिक स्वीकृति

● जशपुर

जशपुर जिले के युवाओं के लिए करियर के नए द्वार खुल गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सतत प्रयासों से पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जशपुर में एनसीसी एयर स्क्वाड्रन की स्वीकृति मिल गई है। यह छत्तीसगढ़ की तीसरी एयर स्क्वाड्रन है, जो युवाओं को वायुसेना और रक्षा सेवाओं में करियर निर्माण का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवचयनित 25 कैडेट्स (13 बालिकाएं, 12 बालक) को एनसीसी बैच लगाकर प्रशिक्षण की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर विंग कमांडर विवेक कुमार साहू, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, श्रीमती गोमती साय, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व में रायपुर के अलावा अन्य हवाई पट्टी युक्त शहरों में भी एयर एनसीसी यूनिट शुरू करने की बात कही थी। इसके परिणामस्वरूप आगडीह हवाई पट्टी, जशपुर को एयर स्क्वाड्रन के लिए स्वीकृति मिली और एक माइक्रोलाइट विमान के जरिए लगभग 100 कैडेट्स को उड़ान का वास्तविक प्रशिक्षण भी दिया गया।

इस प्रशिक्षण के जरिए कैडेट्स को सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के विशेष अवसर मिलेंगे। कई पाठ्यक्रमों में यूपीएससी की आवश्यकता नहीं, केवल एसएसबी साक्षात्कार के जरिए चयन संभव है। साथ ही लड़कियों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं।

यह पहल जशपुर जिले की युवाशक्ति को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी।

जशपुर ने स्वच्छता में रचा इतिहास, मुख्यमंत्री ने दीदियों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वच्छता दीदियों के योगदान को सराहा, जशपुरनगर को देशभर में मिला 10वां स्थान

● जशपुर

जशपुर जिले ने स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जशपुरनगर ने 20,000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों में देशभर में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के लिए ग्राम बगिया में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वच्छता दीदियों को साड़ी, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्वच्छता दीदियों की निष्ठा, सेवा और परिश्रम की सराहना करते हुए उन्हें इस सफलता का असली नायक बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन आज एक जनआंदोलन बन चुका है।

जिले के अन्य नगर निकायों—कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा और कोतबा—ने भी अपने-अपने वर्गों में श्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान किया।

स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिले में बी.टी. रोड निर्माण, वॉल पेंटिंग, सामुदायिक शौचालयों का उन्नयन, वेस्ट मैटेरियल से पार्क निर्माण, साइनेज, पेवर ब्लॉक, कम्पोस्टिंग शेड और रिसाइक्लिंग सेंटर जैसे कई नवाचार किए जा रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों की आत्मा हैं स्वच्छता दीदियाँ हैं, जो डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण जैसे श्रमसाध्य कार्य कर रही हैं।

उक्त कार्यक्रम में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत,पत्थलगांव विधायक एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय,जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव,नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव,कलेक्टर रोहित व्यास शामिल रहे।

सभी जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता दीदियों, नगरीय निकायों और जिलेवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं और निरंतर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया।

'शिक्षा ही सफलता की कुंजी, हर बच्चे को मिले अवसर : श्रीमती कौशल्या साय'

शाला प्रवेश उत्सव में बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत

बालिकाओं को वितरित हुई साइकिलें, पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश

● जशपुर

जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुलदुला में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अर्धांगिनी श्रीमती कौशल्या साय और जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव ने नवप्रवेशी बच्चों का पारंपरिक स्वागत कर निशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिलें वितरित कीं। कार्यक्रम के अंतर्गत "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।

श्रीमती साय ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम बताया।

शौर्य प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि स्मार्ट क्लास जैसी पहल से बच्चों को कठिन विषय सरलता से समझ में आ रहे हैं। उन्होंने विद्यालय में पौधरोपण को प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की शिक्षा देने वाला प्रयास बताया।

जनपद उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में कहा कि आधुनिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों का समन्वय जरूरी है। शाला प्रवेश उत्सव बच्चों के जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहकर संस्कार, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी जगाए—यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। श्री गुप्ता ने सरकार की शिक्षा नीतियों और योजनाओं की सराहना करते हुए सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष राजकुमार सिंह, तहसीलदार राहुल कौशिक, नायब तहसीलदार राजेश यादव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षकगण, विद्यार्थी, अभिभावक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

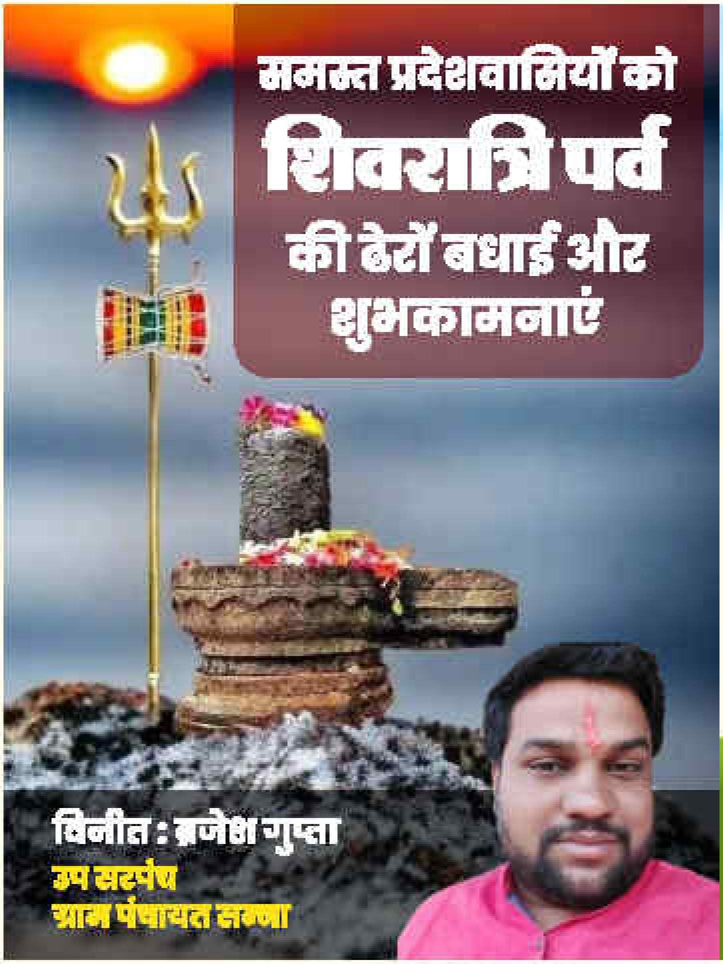

छत्तीसगढ़ CGPSC प्रश्नोत्तरी

1. छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई?
[A] 1998 [B] 1999
[C] 2001 [D] 2000

2. छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है?
[A] रायपुर [B] सिरपुर
[C] सुकमा [D] इनमें से कोई नहीं

3. गंधेश्वर मंदिर कहाँ है?
[A] रायपुर [B] दंतेवाड़ा
[C] सिरपुर [D] रायपुर

4. छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था?
[A] कोसल [B] दक्षिण कोसल
[C] उत्तर कोसल [D] इनमें से कोई नहीं

5. छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया?
[A] उत्तर प्रदेश [B] मध्य प्रदेश
[C] कर्नाटक [D] बिहार

6. जस्टिस मंजूला चिल्लर, जो अभी बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष हैं पहले वो किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थीं?
[A] जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय
[B] पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय
[C] बॉम्बे हाईकोर्ट
[D] गुजरात उच्च न्यायालय

7. झारखंड राज्य में सड़क संपर्क वाले गांवों की संख्या कितनी है?
[A] 10,969 [B] 11,666
[C] 12,343 [D] 17,653

8. इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की "प्रथम राजधानी" कौन सी थी?
[A] पाली [B] तुम्माण
[C] रतनपुर [D] सिरपुर

सही उत्तर –
1: D | 2: B | 3: C | 4: B
5: B | 6: A | 7: B | 8: B

करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी

1. डीआरडीओ के उस कपड़ों के सिस्टम का नाम क्या है जिसे अत्यधिक ठंडे मौसम में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है?
[A] हिमकवच [B] आर्कटिक शील्ड
[C] स्नोगार्ड [D] विंटर वॉरियर

2. डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है?
[A] पुष्कर [B] बीकानेर
[C] जैसलमेर [D] जोधपुर

3. भारत के रबर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रबर बोर्ड द्वारा शुरू की गई दो नई पहलों के नाम क्या हैं?
[A] ग्रीन रबर और RPIS
[B] ISNR (इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर) और INR कनेक्ट
[C] ने-मित्रा और सस्टेनरबर
[D] इनमें से कोई नहीं

4. नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
[A] उत्तर प्रदेश [B] राजस्थान
[C] गुजरात [D] कर्नाटक

5. किस देश के MeerKAT टेलीस्कोप ने Inkathaza नामक एक नई विशाल रेडियो गैलेक्सी की खोज की है?
[A] चीन [B] भारत
[C] ऑस्ट्रेलिया [D] दक्षिण अफ्रीका

6. हाल ही में खबरों में देखी गई लेक सपांका किस देश में स्थित है?
[A] तुर्की [B] ईरान
[C] सऊदी अरब [D] फ्रांस

7. कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कुमारसंभव में कुमार कौन हैं?
[A] कार्तिकेय [B] अभिमन्यु
[C] सनतकुमार [D] अर्जुन

8. निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी?
[A] समुद्रगुप्त [B] चंद्रगुप्त द्वितीय
[C] कुमारगुप्त [D] स्कंदगुप्त

9. पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम (एमआरएलएस) किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था?
[A] भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
[B] रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ)
[C] हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
[D] भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)

10. RS-24 यार्स एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस देश ने विकसित किया है?
[A] फ्रांस
[B] संयुक्त राज्य अमेरिका
[C] रूस
[D] चीन

11. हाल ही में दुर्लभ जीवाश्मित अवशेष किस राज्य में खोजा गया है?
[A] मध्य प्रदेश
[B] झारखंड
[C] बिहार
[D] हरियाणा

12. विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है?
[A] 1 मार्च
[B] 2 मार्च
[C] 3 मार्च
[D] 4 मार्च

13. सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है?
[A] 2 मिनट [B] 4 मिनट
[C] 6 मिनट [D] 8 मिनट

सही उत्तर –
1 : A | 2 : C | 3 : B | 4 : B | 5 : D | 6 : A | 7 : A
8 : A | 9 : B | 10 : C | 11 : B | 12 : A | 13 : D

फ्रांस ने फिलिस्तीन को दी राज्य मान्यता:पश्चिम एशिया की कूटनीति में बड़ा मोड़

● पेरिस / न्यूयॉर्क

पश्चिम एशिया की दशकों पुरानी जटिल कूटनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि फ्रांस सितंबर 2025 में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। यह निर्णय फ्रांस को ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना देता है और वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को जन्म देता है।

मैक्रों का ऐलान और संदेश

मैक्रों ने यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र से पहले सोशल मीडिया मंच X पर की। उन्होंने कहा, "आज की आवश्यकता गाजा में युद्ध का अंत, नागरिकों की सुरक्षा, युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और व्यापक मानवीय सहायता है। हम फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे लेकिन हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "स्थायी शांति तभी संभव है जब फिलिस्तीन, इजराइल की पूर्ण मान्यता दे और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग करे।"

वैश्विक प्रतिक्रियाएं

- फिलिस्तीनी नेतृत्व ने फ्रांस के फैसले को "अंतरराष्ट्रीय न्याय और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के समर्थन" के रूप में सराहा।
- इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फैसले को "आतंक को इनाम" बताते हुए कड़ी निंदा की।
- हमास ने इसे "सकारात्मक कदम" बताते हुए अन्य देशों से इस उदाहरण का अनुसरण करने की अपील की।
- अमेरिका ने इस फैसले को "लापरवाह और समय से पहले" बताया। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि इससे शांति प्रक्रिया को ठेस पहुंचेगी।
- सऊदी अरब ने इसे "विश्व समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी" का सम्मान बताया।
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फिलिस्तीन की राज्यता को "एक अविच्छेद्य अधिकार" करार दिया और युद्धविराम की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रभाव और पृष्ठभूमि

- फिलिस्तीन को अब तक 140 से अधिक देशों की मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह पहला मौका है जब किसी G7 देश ने यह कदम उठाया है।
- गाजा में अब तक 59,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है (स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय)।
- हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 1,200 इजरायली नागरिक मारे गए और 251 बंधक बनाए गए थे।
- UNRWA के अनुसार, गाजा में हर पाँचवाँ बच्चा कुपोषण का शिकार है।

क्या बदलेगा दुनिया में?

फ्रांस के इस ऐतिहासिक कदम से:

- पश्चिम एशिया में शांति की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।
- वैश्विक मंच पर फिलिस्तीन की वैधता और मजबूती बढ़ेगी।
- G7 और संयुक्त राष्ट्र के भीतर नए कूटनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है।
- यह निर्णय केवल फिलिस्तीन के भविष्य को नहीं, बल्कि मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय कानून और विश्व राजनीति के संतुलन को भी एक नया स्वरूप दे सकता है।

यह कदम आने वाले महीनों में पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक कूटनीति को किस दिशा में मोड़ेगा, यह देखना शेष है।

जुलाई माह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं

● वैश्विक इतिहास में जुलाई माह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं

01 जुलाई 1963 – Post Office Savings Bank की स्थापना भारत में हुई।
02 जुलाई 1776 – अमेरिका के कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की।
04 जुलाई 1776 – संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की (अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस)
07 जुलाई 2005 – लंदन बम धमाकों में 52 लोगों की मौत, 700 से अधिक घायल।
14 जुलाई 1789 – बास्तील जेल पर आक्रमण — फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत।
16 जुलाई 1969 – अपोलो 11 मिशन चंद्रमा की ओर रवाना — मानव इतिहास में पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा गया।
20 जुलाई 1969 – नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान बने — 'One small step for man...'
26 जुलाई 1945 – पोट्सडैम घोषणा — जापान के समर्पण के लिए मित्र देशों की चेतावनी।
28 जुलाई 1914 – प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की।

● भारत के इतिहास में जुलाई माह की प्रमुख घटनाएं।

01 जुलाई 1991 – आर्थिक उदारीकरण के तहत भारत में नई औद्योगिक नीति लागू — देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत।
01 जुलाई 2017 – वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू — भारतीय कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव।
07 जुलाई 1896 – महात्मा गांधी ने डरबन में पहली बार सार्वजनिक रूप से 'सत्याग्रह' शब्द का प्रयोग किया।
22 जुलाई 2009 – भारत ने चंद्रयान-1 से चंद्रमा की सतह पर पानी होने का प्रमाण खोजा।
22 जुलाई 2019 – चंद्रयान-2 का सफल प्रक्षेपण — इसरो का ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन।
26 जुलाई 1999 – कारगिल विजय दिवस — भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की।
30 जुलाई 2015 – डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का निधन — भारत के पूर्व राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन'।

● विशेष उल्लेखनीय

04 जुलाई 1902 – स्वामी विवेकानंद का निधन — भारतीय नवजागरण के अग्रदूत।
20 जुलाई 1947 – भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने कार्यभार संभाला।
10 जुलाई 1856 – हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू — समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम।

जुलाई भारत के इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है।

'सुषमा के स्नेहिल सृजन'
छंद – मनहरण घनाक्षरी

'आशुतोष' नीलकंठ

आशुतोष कंठ नीला,
बाघाम्बर वस्त्र पीला,
मस्तक शोभित सोम,
त्रिनेत्र विशाल है।

हलाहल शंख पात्र,
पान कर विषपात्र,
भूत प्रेत संग साथी,
नाम महाकाल है।

हिमालय शुभ धाम,
संगिनी पार्वती नाम,
कपर्दी हैं शूलपाणी,
भस्म सने भाल है।

'सुषमा' सर्वज्ञ शिव,
मृत्युंजय शिवा प्रिय,
अर्जी सुन शिवालय,
नंदी द्वार पाल है।

कवयित्री सुषमा प्रेम पटेल,
रायपुर छ. ग.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
GOVERNMENT OF INDIA

PMFME

छत्तीसगढ़ शासन

आत्मनिर्भर भारत

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत नवीन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदाय किया जाता है। निजी सूक्ष्म उद्यमों को परियोजना लागत को 35 प्रतिशत के दर से मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम राशि रू. 10.00 लाख अनुदान) दिये जाने का प्रावधान है।

क्र.	उद्यम	स्वयं का अंशदान	मार्जिन मनी अनुदान	अधिकतम अनुदान (राशि रू. में)
1	2	3	4	5
1	निजी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम	10 प्रतिशत	35 प्रतिशत	10.00 लाख

पात्रता –

1. हितग्राही का उम्र कम से कम 18 वर्ष हो।
2. आवेदक का कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
3. एक परिवार से एक व्यक्ति ही पात्र होगा।

आवश्यक दस्तावेज –

1. आधार कार्ड।
2. पेन कार्ड।
3. बैंक पासबुक/पिछले छः माह के बैंक स्टेटमेन्ट की कॉपी।
4. राशन कार्ड।
5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

योजना अन्तर्गत संभावित उद्योग –

जैसे–चावल आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुरमुरा, लड्डू, केक, वेफर, झारमुढ़ी, चिवड़ा, राईस मुरकू, हालर मिल, फ्लोर मिल (आटा चक्की), दाल मिल, तेल मिल, मशाला उद्योग, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट, नमकीन, आलू चिप्स, बनाना चिप्स, गुड़ उद्योग, टमाटर सॉस, सत्तू, अचार, पापड़ निर्माण, काजू प्रोसेसिंग, चाय प्रोसेसिंग, टाऊ प्रोसेसिंग, कोदो, कुटकी, मक्का प्रोसेसिंग एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कक्ष क्र. 128, 129, कलेक्ट्रेट परिसर, जशपुर में या ऑनलाईन आवेदन pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/login में की जा सकती है।

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
जिला–जशपुर (छ.ग.)

मो.न.– 9926480995, 9424180536, 9654450538, 8319973807, 9131521330

बदलते बस्तर की नई तस्वीर

327 गांवों में
नियद नेल्ला नार योजना से तीव्र विकास

350 स्कूलों
में दोबारा शुरू हुई पढ़ाई

278 किलोमीटर
नई सड़कों का निर्माण

11 वृहद
पुलों का निर्माण

140 किलोमीटर
नई रेल लाइन विस्तार की स्वीकृति

1000 नए
मोबाइल टावरों की स्थापना

5,500 से
अधिक घरों का विद्युतीकरण

40,000 से
अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत रोजगार अवसर

3202 नए
बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन

5,500 प्रति
मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता का भुगतान

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

RO No.- 13342_1

स्वामी, प्रकाशक, संपादक - श्रीमती [illegible], [illegible] वार्ड क्रमांक 13 जशपुर, जिला जशपुर पिन कोड - 496331 छत्तीसगढ़ से प्रकाशित, आसना पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड [illegible] चौक रायपुर, छ.ग. से मुद्रित, (प्रबंध [illegible] संपादक) RNI CHHHIN/25/A0341 (न्याय क्षेत्र जशपुर होगा।)